

# लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 322 ● भिलाई, मंगलवार 07 जुलाई 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

## संक्षिप्त समाचार

**इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में निर्माणाधीन दो मंजिला इमारत ढही**

चंडीगढ़। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में शाम एक निर्माणाधीन दो मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के समय भवन के अंदर सात लोग मौजूद थे। इनमें पांच मजदूर और इमारत को लीज पर लेने वाले दो पार्टनर शामिल थे। हादसा प्लाट नंबर 28/9, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में शाम करीब 4-15 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार तरुण कौशिक और तरुण जैन ने करीब 10 दिन पहले ही इस इमारत को लीज पर लिया था। यहां कबाड़ का कारोबार शुरू किया जाना था और इसी के तहत भवन में मरम्मत व निर्माण कार्य चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मजदूर ग्राउंड फ्लोर की एक दीवार को मरम्मत कर रहे थे। इसी दौरान पुरानी और जर्जर दीवार अचानक ढह गई और कुछ ही सेकंड में पूरी दो मंजिला इमारत भरभराकर गिर पड़ी। मलबा गिरने से अंदर मौजूद सभी सात लोग दब गए और उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। मलबे में दबे एक मजदूर ने किसी तरह खुद को बाहर निकाला और तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।

**गुरुग्राम में यू-टर्न लेते समय ट्रक ने कार को मारी टक्कर**

गुरुग्राम। सेक्टर 93 चौकी क्षेत्र में अल सुबह साढ़े तीन बजे एलान मॉल के पास पटीदी रोड पर यू टर्न ले रही हंडई और कार को पीछे से आए ट्रक ने सीधी टक्कर मार दी। हादसे में कार कई बार पलटी खाई। इसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। एक युवक की हालत गंभीर है। जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक समेत मीके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, रोहतक के लाखन माजरा क्षेत्र के खरैटी गांव निवासी 24 वर्षीय राहुल गिल अपने मम्मे भाई सोनीपत के शेखपुरा निवासी 25 वर्षीय उमंग और तीन अन्य दोस्तों के साथ में शनिवार को काम की तलाश में गुरुग्राम आए थे। चढ़ते वह लोग कैंटीन खोलना चाहते थे।

**चलती बस पर पहाड़ी से गिरा विशाल पत्थर, एक की मौत**

चम्बा। हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। यहां, भरमौर से चम्बा आ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस पर गैहरा के पास सुबह करीब 7 बजे पहाड़ी से अचानक एक विशाल पत्थर आ गिरा। पत्थर बस को छत तोड़ते हुए सीधे अंदर जा चुका, जिससे बस में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के समय बस में करीब 40 के करीब यात्री सवार थे प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस हादसे में एक व्यक्ति को मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार यात्री गंभीर रूप से घायल बताये जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस में सवार अधिकांश लोग शिव पूजन समारोह से वापस लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और प्रशासन की टीमों मौके पर पहुंचीं और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

पुणे में भूस्खलन से घर दबे, मुंबई-पुणे रूट पर यातायात ठप

## महाराष्ट्र में बारिश का कहर: 13 लोगों की मौत कई घायल

महाराष्ट्र/एजेंसी

महाराष्ट्र में मानसून का प्रकोप अपने चरम पर है। भारी बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस आपदा में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर है, जबकि पुणे के पाटन गांव में भूस्खलन के कारण एक घर मलबे में दब गया, जिससे एक व्यक्ति की जान चली गई और दो अन्य लापता बताए जा रहे हैं। पुणे जिले के पाटन गांव में सोमवार तड़के भारी बारिश के चलते तीन बार भूस्खलन हुआ। इनमें से एक घटना में परिवार का एक घर मलबे में पूरी तरह समा गया। लोनावला डिवीजन के डीएसपी गजानन तोम्पे ने बताया कि घटना के वक्त घर में तीन लोग मौजूद

थे। फिहाल एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और बचाव दल मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा, घोरवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास एक निजी बस के जलभरण में पंसेन पर एनडीआरएफ की टीम ने 37 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। भारी बारिश ने मुंबई और पुणे के बीच रेल संपर्क को पूरी तरह तोड़ दिया है। सेंट्रल रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने बताया कि कर्जत-लोनावला के बीच भोर घाट सेक्शन में ठाकुरवाड़ी और मंकी हिल के पास भूस्खलन हुआ है। रेलवे की तीनों मुख्य लाइनें- मुंबई की ओर जाने वाली अप समा, पुणे की ओर जाने वाली डाउन लाइन और मिडिल लाइन प्रभावित हुई हैं। इस वजह से 16 ट्रेनें रद्द और 9 ट्रेनें



का मार्ग बदला गया है। रद्द होने वाली प्रमुख ट्रेनें में इंद्रावणी एक्सप्रेस, इंटरसिटी, डेकन एक्सप्रेस, डेकन क्वीन, प्रागति एक्सप्रेस, धुले एक्सप्रेस और पुणे-सीएसएमटी सिंदगाड एक्सप्रेस शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जानने की अपील की है। भारी बारिश और भूस्खलन के

चलते मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और पुराने मुंबई-पुणे हाईवे को अर्निधितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। टनल-2 के पास भूस्खलन होने के बाद पुणे जाने वाले मार्ग को खंडित किया गया है। मावल और ताम्हिनी घाट के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति है। पुणे और मुंबई को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग भी प्रभावित हुए हैं।

'मिसिंग लिंक' सेक्शन के बीच एक कंक्रीट का खंभा सड़क पर गिर गया है, जिससे यातायात पूरी तरह ठप है। ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि जब तक हालात सामान्य न हों, पुणे और मुंबई के बीच यात्रा न करें। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम स्थिति की निगरानी कर रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर मुंबई, पुणे, ठाणे और पालघर जिलों के सभी सरकारी, निजी और नगर निगम के स्कूलों-कॉलेजों में सोमवार को छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए अरिज और पुणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने बताया कि मावल और ताम्हिनी घाट के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिससे पुणे और मुंबई को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग भी प्रभावित हुए हैं।

**स्कूल-कॉलेज बंद, 20 ट्रेनें रद्द, 17 फ्लाइट कैसिल**  
**महाराष्ट्र में रेड अलर्ट**

महाराष्ट्र में मानसून ने रखर पकड़ ली है और लगातार तीसरे दिन हो रही मुस्तावार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सबसे ज्यादा असर मुंबई, पुणे और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच प्रशासन ने लोगों से बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलने की अपील की है। कई निजी कंपनियों ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है, जबकि सरकारी, निजी और नगर निगम के सभी स्कूल-कॉलेजों में सोमवार को छुट्टी घोषित कर दी गई। भारी बारिश के चलते मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर कर्जत-लोनावला के भोर घाट सेक्शन में दो रेलखंभे पर तैरताइत हाई, जिससे तीनों रेलवे लाइनें प्रभावित हो गईं। सुरक्षा कारणों से 20 ट्रेनें को रद्द करना पड़ा। जबकि कई अन्य ट्रेनें का संचालन प्रभावित रहा।

योगी कैबिनेट का अहम फैसला

**अब भगवान परशुराम पुरी कहलाएगा जलालाबाद.....**

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक ली। जिसमें कुल 28 प्रस्ताव पेश किए गए, इनमें से 27 प्रस्तावों को मॉनिट्रिंग की मंजूरी मिल गई। वहीं एक मदरसे से संबंधित (15वां) प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है। कैबिनेट ने होमगार्ड स्वयंसेवकों को पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करने, अन्य विभागों में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती, कानपुर, फतेहपुर और गाजियाबाद में विश्वविद्यालय के स्थापना, शाहजहाँपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर 'परशुरामपुरी' रखने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए हैं।



उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में कैबिनेट ने प्रदेश में निवेश, उद्योग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन 2026 और डेटा सेंटर नीति को मंजूरी दे दी है।

पीएम मोदी आज से 3 देशों के दौरे पर

**पीएम मोदी ने कहा-कूटनीतिक साझेदारियों के साथ रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना मकसद.....**

नई दिल्ली। पीएम मोदी आज से तीन देशों के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के लिए नई दिल्ली से रवाना हो गए हैं। भारत का मकसद इन तीनों देशों के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने के साथ साथ इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करना भी है। इस दौरे की शुरुआत इंडोनेशिया से होगी। यह यात्रा भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर जारी कूटनीतिक, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड

की छह दिवसीय यात्रा पर निकल गए हैं। इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियातो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में रहेंगे। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति प्रबोवो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता में मुख्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे और सांस्कृतिक-ऐतिहासिक शहर योग्याकर्ता भी जाएंगे। इंडोनेशिया मलक्का जलडमरूमध्य की सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इंडोनेशिया दौरे के बाद पीएम का दूसरा पड़व 8 से 10 जुलाई ऑस्ट्रेलिया के



मेलबर्न है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में एफ्टीए लागू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में दोनों नेताओं का विषय वार्ता में रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, शिक्षा, स्किल एवं मोबिलिटी, क्रिस्टिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, खेल और स्पोर्ट्स साईंस जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर रहेगा।

पीएम मोदी दौरे का अंतिम चरण 10-11 जुलाई न्यूजीलैंड के ऑकलैंड है। न्यूजीलैंड के साथ एफ्टीए पर हस्ताक्षर हो चुका है लेकिन अभी लागू नहीं किया गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और आर्थिक सहयोग के साथ-साथ हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन पर भी चर्चा होने की संभावना है। यह 40 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। भारत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सरकारों के समक्ष भारत-विरोधी गतिविधियों, खासकर खालिस्तान समर्थकों द्वारा हिंसक अतिवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का मुद्दा भी मजबूती से उठाएगा।

बीजेपी अध्यक्ष का कांग्रेस और उमर सरकार पर हमला

**एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का सपना साकार**

नई दिल्ली/एजेंसी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर जम्मू-कश्मीर पहुंचे। मिश्रीवाला में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर त्याग, बलिदान और वीरता की भूमि है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में शांति, विकास और सुशासन का नया दौर शुरू हुआ है। नितिन नवीन ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन करोड़ों देशवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है।



उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का सपना साकार हुआ है। साथ ही माता वैष्णो देवी की कृपा और डोगरा वीरों के बलिदान को भी नमन किया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रदेश में व्यापक

बदलाव आया है। उनके अनुसार अब लाल चौक समेत पूरे जम्मू-कश्मीर में तिरंगा शान से लहराता है, अलगाववाद, पत्थरबाजी और बंद की राजनीति समाप्त हो चुकी है तथा विकास और निवेश का माहौल बना है। नितिन नवीन ने कांग्रेस पर राष्ट्रविरोधी तत्वों का समर्थन करने का आरोप लगाया। वहीं, जम्मू-कश्मीर की उमर अब्दुल क़रार पर जम्मू क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सभी क्षेत्रों और समुदायों के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सड़क, हवाई अड्डों और बुनियादी ढांचे के विकास को गति दी है।

पति की हत्या के बाद बाथरूम में खुद खोदी कब्र

आगरा। शराबी पति के रोज-रोज के जुल्मों से तंग आकर एक पत्नी ने खौफनाक कदम उठा लिया। उसने अकेले ही अपने पति की हत्या कर दी और लाश को घर के ही बाथरूम में दफना दिया। राज छिपाने के लिए उसने लाश के ऊपर मिट्टी और गिट्टी डाली और फिर मिस्त्री बुलाकर वहां पक्का फर्श बनवा दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया है, जबकि पूछताछ के बाद मिस्त्री और मजदूर को छोड़ दिया गया। हिरासत में रहने के दौरान महिला यतभर रोती रही और उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वहीं, पुलिस ने बाथरूम की खुदाई करवाकर करीब 45 दिन पुराना कंकाल बरामद कर लिया है, जिसका अब डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है।

पहलगाम आतंकी हमला: एनआईए की बड़ी कार्रवाई

**सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आतंकी हाफिज सईद नाम भी शामिल**

नई दिल्ली/एजेंसी

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी और लश्कर-ए-तैयबा व टीआरएफ के संस्थापक हाफिज सईद के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। सोमवार को जम्मू स्थित एनआईए की स्पेशल कोर्ट में यह चार्जशीट पेश की गई। एजेंसी ने हाफिज सईद को व्यक्तिगत तौर पर आरोपित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा व उसके प्रॉक्सि संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' के प्रमुख के रूप में आरोपी बनाया



है। उस पर भारतीय न्याय संहिता 2023 और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 को विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एनआईए ने उस पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से साजिश रचने का भी

आरोप लगाया है। दक्षिण-एशियाई और प्रवासी यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट मूल 1,597 पन्नों की चार्जशीट का विस्तार है। इसमें पाकिस्तान की साजिश, हाफिज सईद की भूमिका और एनआईए द्वारा वैधानिक जांच व ऑन-ग्राउंड खननबी से जुटाए गए पुरखे सभूतों का विवरण दिया गया है। इससे पहले 15 दिसंबर 2025 को दाखिल की गई चार्जशीट में एनआईए ने पाकिस्तानी हैंडलर आतंकी साजिद जदू के अलावा जुलाई 2025 में 'ऑपरेशन महदेव' के दौरान मारे गए तीन आतंकीयों और दो गिरफ्तार आरोपियों को नामजद किया था।

राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला: चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर

**कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई**

नई दिल्ली/एजेंसी

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के खुलासे के बाद मंचे देशव्यापी बवाल के बीच सोमवार को हुई ट्रस्ट की आपात बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुई। करीब चार घंटे तक चली इस हाई-प्रोफाइल बैठक में न केवल मंदिर प्रशासन से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर मंथन हुआ, बल्कि ट्रस्ट के शीर्ष नेतृत्व में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़े इस मामले पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थीं। राम मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा और गोपनीयता के बीच हुई बैठक को अध्यक्षता महंत नृत्य गोपाल दास ने की। बैठक के बाद ट्रस्ट ने पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के

इस्तीफे स्वीकार करने की पुष्टि की। साथ ही कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ट्रस्ट ने साफकिया कि चढ़ावा चोरी मामले को जांच पूरी होने तक प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि ने चोरी की घटना को अत्यंत दुःखद और लज्जाजनक बताया हुए दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। उन्होंने मंदिर को बहुमूल्य वस्तुओं के गायब होने संबंधी दावों को अप्रत्याह करार दिया और कहा कि सभी 2800 पंजीकृत वस्तुएं सुरक्षित हैं। ट्रस्ट ने ब्रह्मालुओं से अप्रत्याहों से बचने और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखने की अपील भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरि ने



बताया कि जिनको शक हो वह राम मंदिर जाकर चढ़ावा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि ट्रस्ट को लेकर बेवजह अप्रत्याहों पर ध्यान न दिया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंद देवगिरि ने कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई वह लोग ज्ञान दे रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष

गोविंद देव गिरि ने चढ़ावा चोरी की घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए इसे पूरे समाज के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति बताया है। उन्होंने कहा कि जिस मंदिर के लिए लोगों ने अपने प्राणों और परिवारों की परवाह नहीं की, वहां ऐसी असाधारण घटना होना दुःखद है। इसी आपात स्थिति को देखते हुए जो बैठक पहले 11 जुलाई

को होनी थी, उसे प्रीपोन करके 6 जुलाई को ही आयोजित किया गया, जिसमें कोरम पूरा रहा और अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास समेत निर्माहो अखाड़े के संत दिनेंद्र जी महाराज भी उपस्थित रहे। गोविंद देव गिरि ने स्पष्ट किया कि चढ़ावा चोरी की घटना से चंपत राय को बहुत गहरी वेदना पहुंची थी। उनके मन में यह बात थी कि जब तक इस मामले में न्याय नहीं हो जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उन्हें सजा नहीं मिल जाती, तब तक वे पद पर नहीं रहेंगे और इसी सोच के साथ उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया। कोषाध्यक्ष के अनुसार, न्यास के संविधान के नियमों के मुताबिक त्यागपत्र देते ही उसे स्वीकार मान लिया जाता है, इसलिए मूल प्रोसेस को आधार मानकर इसे मंजूर किया गया।

**कर्मियों को दूर कर व्यवस्था को पारदर्शी बनाएंगे नए महासचिव कृष्ण मोहन**

राम मंदिर ट्रस्ट के नवनिर्भूत महासचिव कृष्ण मोहन ने कार्यभार संभालते ही अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि पूर्व में प्रबंधन और संचालन के स्तर पर कुछ कमियां और लूप होल्स रह गए थे, जिन्हें पूरी तरह से ठीक किया जाएगा। हस्तिया घटनाक्रमों के कारण समाज में न्यास की छवि को जो नुकसान पहुंचा है, उसे सुधारने के लिए सभी न्यायी मिलकर काम करने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि वे सभी को दूर कर व्यवस्था को पारदर्शी बनाएंगे और लूप होल्स को दूर कर देंगे। उन्होंने कहा कि वे सभी को दूर कर व्यवस्था को पारदर्शी बनाएंगे और लूप होल्स को दूर कर देंगे। उन्होंने कहा कि वे सभी को दूर कर व्यवस्था को पारदर्शी बनाएंगे और लूप होल्स को दूर कर देंगे।



संक्षिप्त समाचार

बंदूक छोड़ विकास की राह पर बढ़े मड़कम भीमा, शासकीय योजनाओं ने बदली जिंदगी

रायपुर। जिले में शासन की पुनर्वास नीति और जनकल्याणकारी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। कौटा विकासखंड के ग्राम पंचायत पोलमपल्ली निवासी मड़कम भीमा की कहानी इस परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है, जिन्होंने हिंसा और भय के रास्ते को छोड़कर विकास और लोकतंत्र की मुख्यधारा को अपनाया। जिला प्रशासन, सुरक्षा बलों और शासन की समन्वित पहल ने उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक पुनर्स्थापित होने का अवसर प्रदान किया। मुख्यधारा में लौटने के बाद जिला प्रशासन ने मड़कम भीमा को शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन को नई दिशा दी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आर्थिक सहायता से उनका पक्का आवास बनकर तैयार हुआ, जिसने उनके परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का आधार दिया। यह पहल न केवल एक घर उपलब्ध कराने तक सीमित रही, बल्कि उनके जीवन में स्थायित्व और विश्वास को नई भावना भी लेकर आई। आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा उन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से जोड़ा गया। गांव के विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी करते हुए उन्होंने सम्मानजनक मजदूरी अर्जित की, जिसकी राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंची। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, बल्कि आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने की नई प्रेरणा भी मिली। मड़कम भीमा की सफलता की यह कहानी बताती है कि सुकमा जिला प्रशासन की संवेदनशील पहल, प्रभावी पुनर्वास नीति और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज को मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रहा है। यह उदाहरण जिले के युवाओं के लिए एक सकारात्मक संदेश है कि विकास, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का मार्ग ही उज्वल भविष्य की ओर ले जाता है तथा शासन हर कदम पर उनके साथ खड़ा है।

जिला पंचायत सीईओ ने ली प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के प्रगति की समीक्षा बैठक

रायपुर। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा के लिए जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सीएसपीडीसीएल के अधिकारियों एवं जिले के सभी बैंकों के नोडल अधिकारियों ने सहभागिता की। बैठक में योजना की बैंकवार प्रगति की समीक्षा की गई। सीईओ विश्वरंजन ने सभी बैंकों को स्वयं स्रोत आवंटनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंक अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुंच बनाकर आवेदन प्राप्त करें तथा योजना के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाएं। जिला पंचायत सीईओ ने सभी बैंकों को प्रगति में सुधार लाने, लॉसित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा स्वीकृत प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर योजना के निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभाग एवं बैंक गंभीरता एवं सक्रियता के साथ कार्य करें इस अवसर पर एलडीएम मोहम्मद मोफिज सहित अन्य अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े रहे।

आकाशीय बिजली से बचाव के लिए जिला प्रशासन की अपील

रायपुर। वर्षा ऋतु के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में संभावित वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने जिलेवासियों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। नागरिकों से कहा गया है कि मौसम खराब होने, तेज गरज-चमक या बिजली कड़कने की स्थिति में लापरवाही न करें और तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर शरण लें। गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, खेत, पहाड़ी क्षेत्र, नदी-तालाब एवं अन्य जलाशयों के आसपास जाने से बचें। साथ ही पेड़ों के नीचे खड़े न हों, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने का शीघ्र अधिक रहता है। ऐसी स्थिति में किसी पक्के भवन या पूरी तरह बंद वाहन में शरण लेना सुरक्षित उपाय है। मौसम विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी चेतावनियों का पालन करें तथा अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। यदि कोई व्यक्ति खुले स्थान पर फंस जाए और तत्काल सुरक्षित स्थान तक पहुंचना संभव न हो, तो दोनों पैरों को आपस में मिलाकर नीचे झुक जाएं, सिर नीचे रखें तथा हाथ घुटनों पर रखें। इस दौरान जमीन पर पूरी तरह न लेटें और अन्य लोगों से उचित दूरी बनाए रखें, ताकि संभावित खतरे को कम किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि आकाशीय बिजली से प्रभावित व्यक्ति को ठंडा पानी पीने से सुरक्षित होता है। ऐसी स्थिति में बिना समय गंवाए 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दें अथवा प्रभावित व्यक्ति को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाएं। यदि व्यक्ति की सांस या नाड़ी नहीं चल रही हो, तो प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा तुरंत सीपीआर शुरू करें और गंभीर स्थिति में शीघ्र अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वर्षा ऋतु में मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लें और सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करें। प्रशासन का संदेश है कि जब गरज सुनाई दे, तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं। आपकी सतर्कता ही आपका जीवन बचा सकती है।

दूधाधारी मठ की 30 एकड़ जमीन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, 20 साल बाद भी नहीं मिला बदले में भूखंड

रायपुर। राजधानी रायपुर के अंतरराज्यीय बस स्टैंड के निर्माण के लिए करीब दो दशक पहले दूधाधारी मठ ट्रस्ट से ली गई 30 एकड़ जमीन के बदले अब तक दूसरी जमीन नहीं मिलने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2007-08 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की पहल पर रायपुर में अंतरराज्यीय बस स्टैंड निर्माण के लिए दूधाधारी मठ ट्रस्ट ने अपनी 30 एकड़ जमीन देने पर सहमति दी थी। समझौते के तहत ट्रस्ट को नवा रायपुर में जमीन देने और बस स्टैंड परिसर में बनने वाले कॉम्प्लेक्स की आधी दुकानें देने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद ट्रस्ट ने जमीन नगर निगम को सौंप दी।

सुशासन, तकनीक, कृषि, पर्यटन और विकासपरक राजनीति पर हुआ गहन मंथन

चिंतन शिविर 3.0 से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को मिलेगी नई दिशा

चिंतन शिविर से निकले विचार बन रहे सुशासन और विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला

रायपुर/ संवाददाता

विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दीर्घकालिक रणनीति, सुशासन की और अधिक प्रभावी बनाने तथा भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप प्रशासनिक क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से सुशासन एवं अभिसरण विभाग तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय 'चिंतन शिविर 3.0' का सफलतापूर्वक समापन हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तथा देश के प्रतिष्ठित नीति विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और

विषय विशेषज्ञों ने शासन, विकास और जनसेवा के विभिन्न आयामों पर व्यापक विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि चिंतन शिविर अब केवल विचारों के आदान-प्रदान का मंच नहीं रह गया है, बल्कि शासन व्यवस्था में ठोस सुधारों का प्रभावी माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक, पारदर्शी, तकनीक-संचालित और नागरिकों की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील प्रशासन विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चिंतन शिविर 3.0 से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को नई दिशा देंगे तथा इन्हें शीघ्र ही नीतिगत एवं प्रशासनिक पहलों के रूप में लागू किया जाएगा। दूसरे दिन आयोजित 'सतत समृद्धि के इंजन के रूप में पर्यटन' विषयक सत्र में वरिष्ठ आईएसएस अधिकारी एवं पर्यटन नीति विशेषज्ञ श्री सुमन बिब्ल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक, जनजातीय और सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में देश का



अग्रणी हाई-वैल्यू, लो-इम्पैक्ट पर्यटन गंतव्य बनने की अपार क्षमता रखता है। उन्होंने पर्यटन अवसरचना, सामुदायिक भागीदारी, निवेश, उत्तरदायी पर्यटन और सुशासन आधारित पर्यटन मॉडल पर बल दिया। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर क्षेत्र, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई

आर्थिक क्षमता के अनुरूप विकास रणनीति तथा जिला-स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद आधारित नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने 'अमृत प्रयास', 'बनयान रिवोल्यूशन' और सहभागी शासन की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए कहा कि जिला-केंद्रित विकास मॉडल उद्यमिता, रोजगार, कृषि परिवर्तन, स्थानीय नवाचार और जन-क्षमता के विकास को नई गति देगा तथा विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 क्षेत्रों के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। समापन सत्र में डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन, प्रभावी नीति-क्रियान्वयन, नेतृत्व विकास तथा लोक प्रशासन के विभिन्न आयामों पर अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले दो चिंतन शिविरों में प्राप्त सुझावों को राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से पहलों के निपटारे की प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और समयबद्ध हुई है।

प्रदेश में बढ़ते अपराध के पीछे कई कांग्रेसी नेताओं का हाथ-डॉ. विजय शंकर मिश्रा.....

छत्तीसगढ़ की फिजा खराब करने कई कांग्रेसी नेता अब अपने घर में काम करने वालों को भी अपराधी बनाने लगे

रायपुर/ संवाददाता

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ विजय शंकर मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते अपराध के पीछे कई कांग्रेसी नेता और उनके कार्यकर्ताओं का हाथ होता है। छत्तीसगढ़ में लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें यह कांग्रेसी नेता नहीं चाहते। अपराध करने की आदि हो चुकी कांग्रेस पार्टी के कई नेता अब अपने घर में काम करने

वाले लोगों को भी अपराधी बनाने का काम कर रहे हैं और उन्हें प्रदेश में अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक से मोबाइल लुटने वाला आरोपी का एक सीनियर कांग्रेस लीडर के घर आना-जाना था। अपराधी के पिता भी कांग्रेस नेता के घर काम करते हैं। जो इस बात को साबित करती है कि हर अपराध के पीछे कांग्रेस एवं कांग्रेसी नेताओं का हाथ होता है।

5 भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजय शंकर मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों (जैसे श्व) और स्थानीय पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की गई है। इनमें कई कांग्रेसी नेता का नाम बड़े घोटालों



से लेकर स्थानीय स्तर के वित्तीय और अन्य अपराधों के मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कोयले घोटाले से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ निदेशालय (श्व) द्वारा कब्रालीसगढ़ में करीब 540 करोड़ के कथित कोयला लेवी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश

कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल का नाम आया। श्व ने इनके परिसरों पर छापेमारी की। कांग्रेस पार्टी ने अवैध कोयला लेवी से वसूला गया पैसा पार्टी फंड और चुनावी खर्चों में इस्तेमाल किया। इसके साथ ही सतीश अग्रवाल (भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पूर्व अध्यक्ष) और आर.पी. सिंह (कांग्रेस प्रवक्ता) के ठिकानों पर भी कथित तौर पर घोटाले की राशि का लाभार्थी होने के संदेह में जांच और छापेमारी की गई थी।

3 किलोवाट रुफ टॉप सोलर संयंत्र से बिजली बिल हुआ शून्य, डबल सब्सिडी से मिली बड़ी राहत

कबाड़ी दुकानों पर पुलिस की औचक जांच, दस्तावेज खंगाले

रायपुर। जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने शुक्रवार को कबाड़ी दुकानों में विशेष जांच अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक ओ.पी. शर्मा के निर्देशन में जिले के विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों में संचालित कबाड़ी दुकानों की औचक चेकिंग कर दस्तावेजों की जांच की गई तथा संदेहास्पद सामानों का सत्यापन किया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने कबाड़ी व्यवसायियों के व्यावसायिक लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर और क्रय-विक्रय से संबंधित दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। इसके साथ ही दुकानों में रखे कबाड़ का मिलान कर यह सुनिश्चित किया गया कि कहीं चोरी का माल या प्रतिबंधित सामग्री तो नहीं रखी गई है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अनीता चौधरी बनीं ऊर्जादाता.....

3 किलोवाट रुफ टॉप सोलर संयंत्र से बिजली बिल हुआ शून्य, डबल सब्सिडी से मिली बड़ी राहत

रायपुर/ संवाददाता प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ आम नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त पहल से संचालित इस योजना का लाभ लेकर सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत कंठी की निवासी श्रीमती अनीता चौधरी अब केवल बिजली की उपभोक्ता नहीं, बल्कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कर ऊर्जादाता बन गई हैं। श्रीमती अनीता चौधरी ने बताया कि पहले हर माह बढ़ते बिजली बिल का भुगतान उनके परिवार के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन जाता था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कराया। इसके बाद उनके घर की बिजली आवश्यकता सौर ऊर्जा से पूरी होने लगी और उनका बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया। उन्होंने बताया कि घरेलू उपयोग के बाद बची अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा

सिंवाई विस्तार, फसल विविधीकरण और विभागीय अभिसरण पर दिया जोर

बस्तर में कृषि विकास को मिलेगी गति: कृषिमंत्री रामविचार नेताम

कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं उद्यानिकी विभागों की योजनाओं की संभाग स्तरीय समीक्षा

रायपुर/ संवाददाता

कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने शुक्रवार को बीजापुर कलेक्टरेट सभाकक्ष में बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं सुकमा जिलों के कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों का निर्देशित किया कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करें तथा शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित करें। कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि अल-नीनो की संभावित परिस्थितियों को लेकर किसानों में किसी प्रकार का भ्रम या भय उत्पन्न न किया जाए। किसानों को वैज्ञानिक सलाह, उन्नत



तकनीकों तथा फसल प्रबंधन के माध्यम से बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने उपलब्ध पू-जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए नलकूप, कुएं एवं अन्य सिंचाई साधनों का विस्तार कर सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने धान के साथ-साथ मका, मूंग, उड़द, मूंगफली, श्रीअन्न तथा अन्य वैकल्पिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया। दंतेवाड़ा जिले में मका उत्पादन के सफल मॉडल को अन्य क्षेत्रों में भी अपनाने के निर्देश दिए। श्री नेताम ने कहा कि बस्तर

क्षेत्र में उत्पादित श्रीअन्न (मिलेट्स) के बेहतर विपणन की व्यवस्था विकसित की जाए। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मूल्य संवर्धन कर ऑनग्राइंडी केंद्रों में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाए। उन्होंने दलहन एवं तिलहन फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को बढ़ावा देने, बीज प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार करने तथा रबी फसलों के रकबे में वृद्धि हेतु सौर सिंचाई पंपों का अधिकतम उपयोग

सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों को रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी विशेष बल दिया। कृषि मंत्री ने पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए मोबाइल वेटेनरी यूनिट एवं टोल फ्री नंबर 1962 का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं

सुकमा जिलों में कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी एवं मत्स्य विभागों के समन्वय से एकीकृत कृषि प्रणाली (इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मत्स्य पालन विभाग को एकीकृत मत्स्य पालन मॉडल विकसित करने, किसान क्रेडिट कार्ड एवं तालाब पट्टा वितरण के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने तथा शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेपों में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए गए। मत्स्य बीज उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा प्रक्षेपों में व्यापक वृक्षारोपण करने पर भी बल दिया गया। उद्यानिकी विभाग की समीक्षा के दौरान कृषि मंत्री ने बीजापुर जिले में हल्दी, नारियल एवं अन्य व्यावसायिक फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए कार्ययोजना तैयार करने, ऑयल पाम योजना का प्रभावी प्रचार-प्रसार करने तथा विभागीय योजनाओं का लाभ अधिकारिक किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय शासकीय भूमि पर प्रदर्शन प्लॉट विकसित कर किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया।

# संपादकीय

एचएसबीसी की मासिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्ष जून में भारतीय वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय मांग में वृद्धि की रफ्तार 39 महीनों में सबसे कमजोर रही। पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त होने को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के फिर से रफ्तार फकड़ने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बुनियादी ढांचों की वृद्धि दर में गिरावट और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ती के साथ अब देश में विनिर्माण गतिविधियों की वृद्धि भी धीमी पड़ गई है।

एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सुचकांक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, विनिर्माण में वृद्धि का आंकड़ा इस वर्ष मई के 55.0 से घटकर जून में 54.2 पर पहुंच गया। यही नहीं, नई कारोबारी मांग और अंतरराष्ट्रीय विक्री की वृद्धि दर सुस्त रहने से वस्तुओं की खरीद, रोजगार सृजन और उत्पादन की रफ्तार भी कम हो गई है। यानी कुछ उपक्रमों को छोड़ दिया जाए, तो देश के ज्यादातर क्षेत्रों की वृद्धि में गिरावट देखी जा रही है, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

# पश्चिम एशिया में संघर्ष की अनिश्चितता के चलते सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था और विनिर्माण ने बढ़ाई चिंता

हालांकि, मंहगाई से राहत दिलाने के लिए तेल कंपनियों ने बुधवार को वाणिज्यिक एलपीजी के 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर पर 183.50 रुपये और बिमान ईंधन में पांच रुपये प्रति लीटर की कटौती की है, लेकिन पिछले दिनों बढ़ाए गए दामों के मुकाबले यह राहत बेहद कम है। इसमें दोराय नहीं कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजे संकट का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय था, लेकिन सवाल यह है कि सरकार की ओर से इसके प्रभाव को कम करने के लिए समय रहते

वैकल्पिक उपाय तलाशने पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ऐसा भी नहीं है कि सरकार इस संकट की संभावनाओं से अनभिज्ञ थी। दावे किए जाते रहे कि रिश्तों को संभालने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, मगर इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम धरातल पर कहीं नजर नहीं आते हैं। एचएसबीसी की मासिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्ष जून में भारतीय वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय मांग में वृद्धि की रफ्तार 39 महीनों में सबसे कमजोर रही। इससे यह अंदाजा लगाया

मुश्किल नहीं है कि भारतीय निर्यात कारोबार पर कितना गहरा असर पड़ा है। सर्वेक्षण में कई कंपनियों ने माना है कि उन्हें हाल के दिनों में नई निर्यातों रोकनी पड़ीं या उन्हें कम कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि लोगों को रोजगार के मोर्चे पर भी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मांग और बाजार की स्थिति को लेकर चिंता के कारण जून में निवेशकों और कारोबारियों का भरोसा भी कमजोर पड़ा है। खासकर विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार को लेकर रुख

असमंजस भरा रहा है, जिस कारण विदेशी निवेश की निकासी का सिलसिला जारी है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य होने को लेकर भी भरोसा घट रहा है। यही वजह है कि अगले एक वर्ष में उत्पादन बढ़ने का अनुमान लगाने वाली कंपनियों का अनुपात इस वर्ष मई की तुलना में जून में आधा रह गया है। वहीं, तेल कंपनियों ने पश्चिम एशिया में संघर्ष से कीमतों में आई तेजी के बाद वाणिज्यिक एलपीजी और विमान ईंधन के दामों में पहली बार कटौती की है।

**राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में दो वर्ष पहले एक इमारत के भूतल में बारिश का पानी भर जाने से वहां कोचिंग सेंटर में मौजूद तीन युवाओं की मौत हो गई थी। ये वे नौजवान थे, जो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर अपने लिए बेहतर रोजगार की जमीन तलाश रहे थे। यहां भी नियमों का उल्लंघन कर निर्माण हुआ था, मगर संबंधित महकमे के अधिकारियों की मिलीभगत से इसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसी तरह का एक मामला हाल में दिल्ली के मालवीय नगर में सामने आया। एक इमारत का अवैध तरीके से विस्तार कर उसे बहुमंजिला होटल बना दिया गया। छह कमरों की विभागीय मंजूरी लेकर 26 कमरे बना दिए गए। इस इमारत में आपात स्थिति के लिए वैकल्पिक निकासी मार्ग और अग्निशमन के पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए थे।**

(सुरेश सेठ)

कानून के मुताबिक, रिहायशी भवनों का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भवन निर्माण से पहले प्रवेश और प्रस्थान के लिए उचित रास्ते बनाए जाने चाहिए। इमारतों में आग लगने या अन्य आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रबंध करना जरूरी है। चाहे सरकार का निर्देश हो या अदालत का फैसला, कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर अपने हित साधने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं, भले ही इससे किसी की जान जोखिम में क्यों न पड़ जाए। सर्वोच्च अदालत ने अपने एक फैसले में कहा कि सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए। सरकार की ओर से भी यह कहा जाता रहा है कि अतिक्रमण करना कानूनी जुर्म है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कानून के मुताबिक, रिहायशी भवनों का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भवन निर्माण से पहले प्रवेश और प्रस्थान के लिए उचित रास्ते बनाए जाने चाहिए। इमारतों में आग लगने या अन्य आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रबंध करना जरूरी है। मगर इन नियम-कानूनों की कौन परवाह करता है? विकास के नाम पर बहुमंजिला इमारतें या भीड़भाड़ वाले स्थलों पर बेतरीब निर्माण प्रथा का प्रतीक बनते-बनते मौत का सूचक बनने लगे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में दो वर्ष पहले एक इमारत के भूतल में बारिश का पानी भर जाने से वहां कोचिंग सेंटर में मौजूद तीन युवाओं की मौत हो गई थी। ये वे नौजवान थे, जो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर अपने लिए बेहतर रोजगार की जमीन तलाश रहे थे। यहां भी नियमों का उल्लंघन कर निर्माण हुआ था, मगर संबंधित महकमे के अधिकारियों की मिलीभगत से इसे नजरअंदाज कर दिया गया।

इसी तरह का एक मामला हाल में दिल्ली के मालवीय नगर में सामने आया। एक इमारत का अवैध तरीके से विस्तार कर उसे बहुमंजिला होटल बना दिया गया। छह कमरों की विभागीय मंजूरी लेकर 26 कमरे बना दिए गए। इस इमारत में आपात स्थिति के लिए वैकल्पिक निकासी मार्ग और अग्निशमन के पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए थे। जब आग लगी तो कई लोग इमारत के अंदर ही फंस गए और उनकी मौत हो गई। इनमें से कई लोग ऐसे थे, जो अपने निकट संबंधियों के उपचार के लिए इस होटल में ठहरे हुए थे। इस घटना के बाद विशेष-प्रदर्शन हुए, सरकार की ओर से पीड़ितों के लिए अनुदान राशि घोषित की गई और फिर अवैध निर्माण को गिराकर

# नियमों की अनदेखी कब तक? अवैध निर्माण और लापरवाही बन रहे हैं मौत का कारण

मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बाद नियमों की अनदेखी और विभागीय लापरवाही की दिल दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलीगंज में सामने आई। जिस इमारत को वर्ष 2016 से ढहाने का नोटिस दिया गया था, वहां गैर-कानूनी ढंग से निर्माण किया गया था। इस व्यावसायिक इमारत में कोचिंग सेंटर भी संचालित किया जा रहा था। यहां लगी आग की घटना में विद्यार्थियों सहित पंद्रह लोगों की मौत हो गई। पहली मंजिल

कहीं होटल में तब्दील कर दिया जाता है, तो कहीं कोचिंग सेंटर संचालित किए जाते हैं। जाहिर है कि यह विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। अदालतों की ओर से ऐसे मामलों में कई बार निर्देश और चेतावनियां दी जा चुकी हैं, लेकिन उन्हें अमल में लाने का जिन पर जिम्मा है, वे आंखें मूंदे बैठे हैं। प्रशासन में छिपी काली भेड़ें नियमों का उल्लंघन करने वालों का रास्ता साफ कर देती हैं। लखनऊ के

है। अलीगंज के मामले में भवन मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और लापरवाही बरतने के आरोप में चार विभागीय अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। कुल मिलाकर सोलह कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। पीड़ित परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। मगर सवाल है कि बार-बार होने वाली इस तरह की घटनाओं के बाद कार्रवाई क्या सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसी नहीं है? ऐसी क्या वजह है कि अवैध तरीके से भवन निर्माण और नियमों की अनदेखी करने वालों को शुरू में नहीं रोका जा सकता? ऐसे लोगों के भीतर कानून का खौफ क्यों नहीं है और क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि वे जो कर रहे हैं, उसे कोई नहीं देख रहा? सवाल है कि देश में 'यह सब चलता है' की मनोवृत्ति कब खत्म होगी?



पर पक्षी और जानवर रखे गए थे। दूसरी मंजिल पर गोदाम था और तीसरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर था। आग गोदाम में लगी और देखते ही देखते पूरी इमारत जल गई। अंदर बैठे छात्र बाहर की ओर भागे, लेकिन निकासी के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं था। बचाव दल ने इमारत की पिछली दीवार तोड़कर कुछ लोगों को बाहर निकाला, तो कुछ छात्र जान बचाने के लिए छिड़कियों से कूद गए।

इसे शासन-प्रशासन की लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि कुछ लोग चंद पैसों के लालच में नियम-कानून का उल्लंघन कर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर देते हैं, जहां आपात स्थिति के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किए जाते। ऐसी इमारतों को

अलीगंज में जिस व्यावसायिक इमारत में आग लगी थी, वह वर्ष 2014 में बनाई गई थी। हैरत की बात है कि नियमों की अनदेखी करने पर निर्माण के दो साल बाद ही इस इमारत को गिराने का नोटिस दे दिया गया था, इसके बावजूद इसका व्यावसायिक इस्तेमाल होता रहा। अब जब आग की घटना में पंद्रह लोगों की जान चली गई, तब जाकर स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। सरकार ने इस घटना की जांच के लिए विशेष दल गठित किया और कानपुर में ऐसे ही 2.2 और कोचिंग संस्थान सील कर दिए गए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नियमों की अनदेखी और अवैध तरीके से निर्माण कितने बड़े पैमाने पर हो रहा

है। अलीगंज के मामले में भवन मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और लापरवाही बरतने के आरोप में चार विभागीय अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। कुल मिलाकर सोलह कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। पीड़ित परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। मगर सवाल है कि बार-बार होने वाली इस तरह की घटनाओं के बाद कार्रवाई क्या सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसी नहीं है? ऐसी क्या वजह है कि अवैध तरीके से भवन निर्माण और नियमों की अनदेखी करने वालों को शुरू में नहीं रोका जा सकता? ऐसे लोगों के भीतर कानून का खौफ क्यों नहीं है और क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि वे जो कर रहे हैं, उसे कोई नहीं देख रहा? सवाल है कि देश में 'यह सब चलता है' की मनोवृत्ति कब खत्म होगी?

नौकरशाही को जब सुविधा केंद्रों में बदला जाता है, तो वे असुविधा केंद्र कैसे बन जाते हैं? जो जनप्रतिनिधि चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की बात करते हैं, जब कभी उनकी तिजोरियों को खंगाला जाता है, तो बेहिसाब संपत्ति का पता चलता है। इससे साफ है कि व्यवस्था में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, जिसकी आग में आम आदमी झुलस रहा है। अगर प्रशासनिक ढांचा ईमानदार हो और कानून तोड़ने वालों को तुरंत दंडित किया जाए, तो कई समस्याएं शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। मगर ऐसा केवल चुनावी घोषणाओं में ही होता है और उसके बाद दिल्ली के राजेंद्र नगर, मालवीय नगर तथा उत्तर प्रदेश के निकासि आर्किटेक्चर जैसी घटनाओं का सिलसिला जारी रहता है। आखिर सरकार और समाज कब जागेंगे कि नियम-कानूनों का उल्लंघन करके हथेलियों पर धन-दौलत की फसल उगाने वालों पर शिकंजा कसा जाए और आम लोगों को भी सम्मान से जीने और अपने सपने पूरे करने का अवसर मिल सके। यह याद रखना चाहिए कि जब तक प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक सुधार नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार और कानून का उल्लंघन कर आमजन की जान को जोखिम में डालने का कुदृष्ट प्रयास भी अनवरत जारी रहेगा।

# दिल्ली मेट्रो का यह फैसला- बढ़ जाएगी यात्रियों की परेशानी

(संतोष कुमार पाठक) लोगों ने रियायती दरों पर पास जारी नहीं करने और दिल्ली मेट्रो के महंगे किराए को भी इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि अब देश की राजधानी में उन्हें विश्वस्तरीय परिवहन व्यवस्था मिलेगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली मेट्रो एक के बाद एक ऐसा फैसला कर रहा है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के विकसित देशों के विकास की कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें दो चीजें आपको कॉमन नजर आएंगी। बेहतर सड़क और शानदार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तो और भी जरूरी है क्योंकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा क़रूड ऑयल और गैस के आयात पर ही खर्च होता है। तमाम ढांचों के बीच कड़वी स्पर्धा तो यही है कि भारत पेट्रोल-डीजल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और हमारी निभरता किस हद तक है, इसका अंदाजा इसी बनावत अमेरिका को लड़ाई के अंश के रूप में हम सबको दिख ही गया है।

बहुत जरूरी है। दिल्ली मेट्रो ने अब यह फैसला किया है कि वो यात्रियों को अब विज्ञापन सिर्फ दिखाएगा ही नहीं बल्कि सुनाएगा भी। यानी जब आप मेट्रो के अंदर सफर करते समय, यह सुनने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है तबकि आप अपने स्टेशन पर उतरने की तैयारी कर सकें तो इस बीच आपको दिल्ली मेट्रो अलग-अलग कंपनियों के विज्ञापन सुनने को मजबूर कर देगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी डेवलपर्स ने अपने नॉन-ऑपरेशन रेवेयू को बढ़ाने के लिए ट्रेन के अंदर ऑडियो विज्ञापन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजुरी दे दी है। हालांकि अधिकारियों ने यह दावा भी किया है कि कंपनियों के ऑडियो विज्ञापन से मेट्रो के अंदर होने वाली ज़रूरी घोषणाओं जैसे-अगला स्टेशन कौन सा है, दरवाजे बंद होने वाले हैं, दरवाजों से हटकर खड़े रहें, यह ट्रेन कहां तक जाएगी पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, आप खुद ही सोचिए।

आपको बता दें कि, वर्तमान में भी दिल्ली मेट्रो को कमाई का सबसे बड़ा जरिया मेट्रो ऑपरेशन यानी इसपर सफर करने वाले यात्रियों से ही आता है। जबकि अन्य कामों यानी गैर ऑपरेशनल गतिविधियों से कुल कमाई का सिर्फ 20 प्रतिशत हिस्सा ही आता है जिसमें हर तरह के विज्ञापन (स्टेशनों के नाम तक बेचना शामिल है) शामिल है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशनों पर दुकानों, क्रियोस्क, एटीएम और पार्किंग से भी कमाई होती है।

जब यात्री खराबकर भरे मेट्रो में (आला स्टेशन जानने के लिए) डिस्प्ले बोर्ड तक नहीं देख पाते हैं, तब मेट्रो में विज्ञापन सुनना चाहता है। लेकिन यह शायद पहला मामला नहीं है जब दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने ऐसा फैसला किया है। यात्रियों की मुश्किलें बढ़ाने वाले फैसलों की तो एक लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है। यात्रियों की सुविधा के लिए एक सिंपल सा स्मार्ट कार्ड जारी किया गया था, जिसे यात्री बड़ी ही आसानी से किसी भी स्टेशन से बनवा सकता था और खराब होने पर लौटा भी सकता था। अब मेट्रो ने बैंक से जुड़े कार्डों को धोपने के लिए साधारण वाला स्मार्ट कार्ड छापना ही बंद कर दिया है। प्लास्टिक वाला पुराना टोकन बंद करके, कागज वाला देने लगे हैं जिससे हर स्टेशन के कस्टमर केंटर पर आपको कागजों का ढेर नजर आएगा। मेट्रो ने नहीं ले जाने वाले सामानों की लंबी-चौड़ी लिस्ट जारी कर रखी है लेकिन उन्हें स्टेशनों पर चलाए जा रहे रेस्टोरेंट में कोई खतरा नजर नहीं आता। हट तो तब से जाती है जब ये अपने स्टेशनों पर बड़े-बड़े शोपिंग लागाकर कंठेय का भी विज्ञापन करते नजर आते हैं। अब ये वक आ गया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को यह बताया जाए कि इसके गठन का मूल उद्देश्य पूरी दिल्ली को जोड़ना था एवं है (अब तो इसमें एनसीआर का इलाका भी शामिल हो गया है) और यात्रियों को तेज और सुगम सार्वजनिक परिवहन को व्यवस्था देना है।

लोगों ने रियायती दरों पर पास जारी नहीं करने और दिल्ली मेट्रो के महंगे किराए को भी इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि अब देश की राजधानी में उन्हें विश्वस्तरीय परिवहन व्यवस्था मिलेगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली मेट्रो एक के बाद एक ऐसा फैसला किया गया था कि स्टूडेंट्स, बुजुर्ग और पत्रकार सहित किसी भी कैटेगरी में किसी को भी रियायती दरों पर कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। थोड़े बहुत विरोध के बाद सबने इसे स्वीकार कर लिया जबकि दिल्ली की सरकारी परिवहन व्यवस्था यानी डीटीसी बसों में कई कैटेगरी के यात्रियों की रियायती दरों पर पास आज भी जारी किए जाते हैं।

लोगों ने रियायती दरों पर पास जारी नहीं करने और दिल्ली मेट्रो के महंगे किराए को भी इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि अब देश की राजधानी में उन्हें विश्वस्तरीय परिवहन व्यवस्था मिलेगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली मेट्रो एक के बाद एक ऐसा फैसला किया गया था कि स्टूडेंट्स, बुजुर्ग और पत्रकार सहित किसी भी कैटेगरी में किसी को भी रियायती दरों पर कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। थोड़े बहुत विरोध के बाद सबने इसे स्वीकार कर लिया जबकि दिल्ली की सरकारी परिवहन व्यवस्था यानी डीटीसी बसों में कई कैटेगरी के यात्रियों की रियायती दरों पर पास आज भी जारी किए जाते हैं।

लोगों ने रियायती दरों पर पास जारी नहीं करने और दिल्ली मेट्रो के महंगे किराए को भी इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि अब देश की राजधानी में उन्हें विश्वस्तरीय परिवहन व्यवस्था मिलेगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली मेट्रो एक के बाद एक ऐसा फैसला किया गया था कि स्टूडेंट्स, बुजुर्ग और पत्रकार सहित किसी भी कैटेगरी में किसी को भी रियायती दरों पर कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। थोड़े बहुत विरोध के बाद सबने इसे स्वीकार कर लिया जबकि दिल्ली की सरकारी परिवहन व्यवस्था यानी डीटीसी बसों में कई कैटेगरी के यात्रियों की रियायती दरों पर पास आज भी जारी किए जाते हैं।

# पारिवारिक और सामाजिक पुनर्वास की मानवीय पहल

(उमेश चतुर्वेदी) देश के एक तिहाई जिलों पर लाल आतंक के रूप में कुख्यात रह नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है। गुहमंत्रि अमित शाह के दावे के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक देश तकरीबन नक्सलमुक्त हो चुका है। इस दौरान सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में ज्यादातर बड़े नक्सली कमांडर मारे जा चुके हैं, या कई ने आत्मसमर्पण कर दिया है।

**केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2700 नक्सली आत्म समर्पण कर चुके हैं। इन पूर्व नक्सलियों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय सहयोग के साथ नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकारें कई सारी योजनाएं चला रही हैं। नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ और झारखंड में आर्थिक सहयोग, रोजगार, घर आदि की सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे नक्सलियों के पुनर्वास को गति मिली है। लेकिन पूर्व नक्सलियों के पुनर्वास का अर्थ है कि वे नक्सलियों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय सहयोग के साथ नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकारें कई सारी योजनाएं चला रही हैं। नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ और झारखंड में आर्थिक सहयोग, रोजगार, घर आदि की सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे नक्सलियों के पुनर्वास को गति मिली है।**

पशुपति यानी नेपाल से लेकर तिरुपति यानी आंध्र के जंगली गलियारे तक तूती बोलने के दौर में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित था। खूंखार नक्सलियों के लिए कुख्यात इसी बस्तर संभाग से छत्तीसगढ़ सरकार ने मानवीय पहल शुरू की है। इसके तहत प्रजनन की उम्र वाले उन नक्सलियों का रिजर्स बैसेकटोमी शुरू किया है। नसबंदी करा चुके लोगों के लिए रिजर्स वासेकटोमी एक तरह से उनकी नसों को फिर से खोलने और उन्हें प्रजनन योग्य बनाने की जटिल प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने इस अनूठी पहल को यूरोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों की मदद से शुरू किया है। 14 जून तक के आंकड़ों के अनुसार, दो चरणों में 73 पूर्व नक्सलियों की नसबंदी खोलने का ऑपरेशन पूरा किया जा चुका है। पहले चरण में 33 पूर्व नक्सलियों को खुशहाल जंदिगी गुजारने को दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो दूसरे चरण में 40 पूर्व नक्सलियों की नसबंदी खोला गया। पहले चरण में जिन 33 पूर्व नक्सलियों की नसबंदी खोलने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, उनमें से 27 के आंगन किसकारियों से गूंज रहे हैं। बस्तर के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के अनुसार,

बस्तर के एक पूर्व नक्सली के घर दो महीने पहले ही बच्चों का जन्म हो चुका है। उस पूर्व नक्सली का परिवार इस बच्ची के साथ अपना पारिवारिक जीवन आनंद से बिता रहा है। आमतौर नसबंदी खोलने के इस जटिल ऑपरेशन के लिए बड़े शहरों और महानगरों के सुविधा संपन्न अस्पतालों में जाना पड़ता है। लेकिन यह पहला मौका है, जब छत्तीसगढ़ के दूर-दूरग के बस्तर संभाग में स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर इस जटिल ऑपरेशन प्रक्रिया को सफलता के साथ अंजाम तक पहुंचाया गया। इस पहल में बस्तर के जिला प्रशासन के साथ ही बस्तर पुलिस और यूरोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों की मदद से शुरू किया है। 14 जून तक के आंकड़ों के अनुसार, दो चरणों में 73 पूर्व नक्सलियों की नसबंदी खोलने का ऑपरेशन पूरा किया जा चुका है। पहले चरण में 33 पूर्व नक्सलियों को खुशहाल जंदिगी गुजारने को दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो दूसरे चरण में 40 पूर्व नक्सलियों की नसबंदी खोला गया। पहले चरण में जिन 33 पूर्व नक्सलियों की नसबंदी खोलने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, उनमें से 27 के आंगन किसकारियों से गूंज रहे हैं। बस्तर के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के अनुसार,

ललित शाह एवं डॉ. योगेश बरापात्रे सहित इंदौर के डॉ. राजेश कुकरेजा, पुणे के डॉ. सागर भालराव और डॉ. राहुल, महाराष्ट्र के नांदेड़ के डॉ. अभिषेक, मुंबई के डॉ. निहार तंबोली और डॉ. पार्थ मातक के साथ ही यूपर के डॉ. राहुल कपूर एवं डॉ. घनश्याम हटवार की टीम ने पूर्व नक्सलियों का सफल ऑपरेशन किया है। इनके सहयोग के लिए छह स्थानीय डॉक्टरों सहित करीब 50 सदस्यों वाली मेडिकल टीम जुटी रही। इतिहास छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल बाकी राज्यों द्वारा नक्सलियों के आर्थिक और जमीनी पुनर्वास नीति से अलग है। विष्णुदेव साय सरकार को इस मानवीय पहल की प्रशंसा मेडिकल जगत के साथ ही समाजविज्ञानी भी कर रहे हैं। इस पहल के तहत शारीरिक और मेडिकल जांच के साथ ही प्रजनन योग्य पाए जाने वाले नक्सलियों के ही ऑपरेशन किए जाते हैं। इनमें चार्लिस साल तक की उम्र वाले पूर्व नक्सलियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। जगदलपुर के महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद के मुताबिक, राज्य सरकार की पहल पर जल्द ही तीसरे चरण का भी शिबिर लगाने की तैयारी है, जिसमें दो दर्जन से ज्यादा पूर्व नक्सलियों के ऑपरेशन किये जायेंगे। छत्तीसगढ़ की यह मानवीय पहल सर्वाधिक नक्सलियों को ना सिर्फ अपने सामाजिक, बल्कि परिवार से भी जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह पहल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा रणनीति से आगे बढ़कर विश्वास निर्माण और सामाजिक-मानवीय पुनर्वास मॉडल के रूप में आगे आ रहा है। ये 73 ऑपरेशन महज चिकित्साकीय आंकड़ा नहीं है, बल्कि इन परिवारों की उम्मीद और सामाज्य जीवन की ओर आगे बढ़ने का भी प्रतीक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड और दूसरे नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकारें भी इस पहल से प्रेरित होंगी। लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक हैं। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

है। लेकिन पूर्व नक्सलियों के पुनर्वास कार्यक्रमों में एक अनूठी मुहिम चलाई जा रही है। यह विशेष मुहिम सिर्फ छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ही चला रही है। इस मुहिम को पारिवारिक और सामाजिक पुनर्वासन कहा जा सकता है। दरअसल नक्सली संगठनों में फोर्ड का कार्य कर रहे नक्सलियों के लिए अमानवीय प्रथा थी। फोर्ड में काम कर रहे कम उम्र के नक्सलियों की अमानवीय तरीके से जबरिया नसबंदी करा दी जाती थी, ताकि नक्सली कार्य करते वक्त वे अपना परिवार न बहू सकें। नक्सली संगठनों में महिला नक्सली भी सक्रिय थीं, उनके बीच रिश्ते पनपने संभव थे। लेकिन उन रिश्तों से बच्चे ना हों, इसलिए पुरुष नक्सलियों को जबरदस्ती नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। जिनमें बहुत सारे नक्सलियों की उम्र बेहद कम थी। लेकिन सरकारी मुहिम के बाद जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया तो उनके मन में भी परिवार बसाने और अपने घर-आंगन में किलकारी गूंजने की चाहत जगी। चूंकि इनकी नसबंदी हो चुकी थी, लिहाजा इन्हें मन-मसोस कर रह जाना पड़ता था। छत्तीसगढ़ सरकार इन्हें सर्वाधिक प्रजनन उम्र वाले नक्सलियों के लिए पारिवारिक तौर पर ज्यादा सक्रिय होने के लिए यह मानवीय पहल शुरू की है।

बस्तर के एक पूर्व नक्सली के घर दो महीने पहले ही बच्चों का जन्म हो चुका है। उस पूर्व नक्सली का परिवार इस बच्ची के साथ अपना पारिवारिक जीवन आनंद से बिता रहा है। आमतौर नसबंदी खोलने के इस जटिल ऑपरेशन के लिए बड़े शहरों और महानगरों के सुविधा संपन्न अस्पतालों में जाना पड़ता है। लेकिन यह पहला मौका है, जब छत्तीसगढ़ के दूर-दूरग के बस्तर संभाग में स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर इस जटिल ऑपरेशन प्रक्रिया को सफलता के साथ अंजाम तक पहुंचाया गया। इस पहल में बस्तर के जिला प्रशासन के साथ ही बस्तर पुलिस और यूरोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों की मदद से शुरू किया है। 14 जून तक के आंकड़ों के अनुसार, दो चरणों में 73 पूर्व नक्सलियों की नसबंदी खोलने का ऑपरेशन पूरा किया जा चुका है। पहले चरण में 33 पूर्व नक्सलियों को खुशहाल जंदिगी गुजारने को दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो दूसरे चरण में 40 पूर्व नक्सलियों की नसबंदी खोला गया। पहले चरण में जिन 33 पूर्व नक्सलियों की नसबंदी खोलने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, उनमें से 27 के आंगन किसकारियों से गूंज रहे हैं। बस्तर के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के अनुसार,

ललित शाह एवं डॉ. योगेश बरापात्रे सहित इंदौर के डॉ. राजेश कुकरेजा, पुणे के डॉ. सागर भालराव और डॉ. राहुल, महाराष्ट्र के नांदेड़ के डॉ. अभिषेक, मुंबई के डॉ. निहार तंबोली और डॉ. पार्थ मातक के साथ ही यूपर के डॉ. राहुल कपूर एवं डॉ. घनश्याम हटवार की टीम ने पूर्व नक्सलियों का सफल ऑपरेशन किया है। इनके सहयोग के लिए छह स्थानीय डॉक्टरों सहित करीब 50 सदस्यों वाली मेडिकल टीम जुटी रही। इतिहास छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल बाकी राज्यों द्वारा नक्सलियों के आर्थिक और जमीनी पुनर्वास नीति से अलग है। विष्णुदेव साय सरकार को इस मानवीय पहल की प्रशंसा मेडिकल जगत के साथ ही समाजविज्ञानी भी कर रहे हैं। इस पहल के तहत शारीरिक और मेडिकल जांच के साथ ही प्रजनन योग्य पाए जाने वाले नक्सलियों के ही ऑपरेशन किए जाते हैं। इनमें चार्लिस साल तक की उम्र वाले पूर्व नक्सलियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। जगदलपुर के महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद के मुताबिक, राज्य सरकार की पहल पर जल्द ही तीसरे चरण का भी शिबिर लगाने की तैयारी है, जिसमें दो दर्जन से ज्यादा पूर्व नक्सलियों के ऑपरेशन किये जायेंगे। छत्तीसगढ़ की यह मानवीय पहल सर्वाधिक नक्सलियों को ना सिर्फ अपने सामाजिक, बल्कि परिवार से भी जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह पहल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा रणनीति से आगे बढ़कर विश्वास निर्माण और सामाजिक-मानवीय पुनर्वास मॉडल के रूप में आगे आ रहा है। ये 73 ऑपरेशन महज चिकित्साकीय आंकड़ा नहीं है, बल्कि इन परिवारों की उम्मीद और सामाज्य जीवन की ओर आगे बढ़ने का भी प्रतीक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड और दूसरे नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकारें भी इस पहल से प्रेरित होंगी। लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक हैं। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

ललित शाह एवं डॉ. योगेश बरापात्रे सहित इंदौर के डॉ. राजेश कुकरेजा, पुणे के डॉ. सागर भालराव और डॉ. राहुल, महाराष्ट्र के नांदेड़ के डॉ. अभिषेक, मुंबई के डॉ. निहार तंबोली और डॉ. पार्थ मातक के साथ ही यूपर के डॉ. राहुल कपूर एवं डॉ. घनश्याम हटवार की टीम ने पूर्व नक्सलियों का सफल ऑपरेशन किया है। इनके सहयोग के लिए छह स्थानीय डॉक्टरों सहित करीब 50 सदस्यों वाली मेडिकल टीम जुटी रही। इतिहास छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल बाकी राज्यों द्वारा नक्सलियों के आर्थिक और जमीनी पुनर्वास नीति से अलग है। विष्णुदेव साय सरकार को इस मानवीय पहल की प्रशंसा मेडिकल जगत के साथ ही समाजविज्ञानी भी कर रहे हैं। इस पहल के तहत शारीरिक और मेडिकल जांच के साथ ही प्रजनन योग्य पाए जाने वाले नक्सलियों के ही ऑपरेशन किए जाते हैं। इनमें चार्लिस साल तक की उम्र वाले पूर्व नक्सलियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। जगदलपुर के महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद के मुताबिक, राज्य सरकार की पहल पर जल्द ही तीसरे चरण का भी शिबिर लगाने की तैयारी है, जिसमें दो दर्जन से ज्यादा पूर्व नक्सलियों के ऑपरेशन किये जायेंगे। छत्तीसगढ़ की यह मानवीय पहल सर्वाधिक नक्सलियों को ना सिर्फ अपने सामाजिक, बल्कि परिवार से भी जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह पहल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा रणनीति से आगे बढ़कर विश्वास निर्माण और सामाजिक-मानवीय पुनर्वास मॉडल के रूप में आगे आ रहा है। ये 73 ऑपरेशन महज चिकित्साकीय आंकड़ा नहीं है, बल्कि इन परिवारों की उम्मीद और सामाज्य जीवन की ओर आगे बढ़ने का भी प्रतीक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड और दूसरे नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकारें भी इस पहल से प्रेरित होंगी। लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक हैं। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

ललित शाह एवं डॉ. योगेश बरापात्रे सहित इंदौर के डॉ. राजेश कुकरेजा, पुणे के डॉ. सागर भालराव और डॉ. राहुल, महाराष्ट्र के नांदेड़ के डॉ. अभिषेक, मुंबई के डॉ. निहार तंबोली और डॉ. पार्थ मातक के साथ ही यूपर के डॉ. राहुल कपूर एवं डॉ. घनश्याम हटवार की टीम ने पूर्व नक्सलियों का सफल ऑपरेशन किया है। इनके सहयोग के लिए छह स्थानीय डॉक्टरों सहित करीब 50 सदस्यों वाली मेडिकल टीम जुटी रही। इतिहास छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल बाकी राज्यों द्वारा नक्सलियों के आर्थिक और जमीनी पुनर्वास नीति से अलग है। विष्णुदेव साय सरकार को इस मानवीय पहल की प्रशंसा मेडिकल जगत के साथ ही समाजविज्ञानी भी कर रहे हैं। इस पहल के तहत शारीरिक और मेडिकल जांच के साथ ही प्रजनन योग्य पाए जाने वाले नक्सलियों के ही ऑपरेशन किए जाते हैं। इनमें चार्लिस साल तक की उम्र वाले पूर्व नक्सलियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। जगदलपुर के महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद के मुताबिक, राज्य सरकार की पहल पर जल्द ही तीसरे चरण का भी शिबिर लगाने की तैयारी है, जिसमें दो दर्जन से ज्यादा पूर्व नक्सलियों के ऑपरेशन किये जायेंगे। छत्तीसगढ़ की यह मानवीय पहल सर्वाधिक नक्सलियों को ना सिर्फ अपने सामाजिक, बल्कि परिवार से भी जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह पहल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा रणनीति से आगे बढ़कर विश्वास निर्माण और सामाजिक-मानवीय पुनर्वास मॉडल के रूप में आगे आ रहा है। ये 73 ऑपरेशन महज चिकित्साकीय आंकड़ा नहीं है, बल्कि इन परिवारों की उम्मीद और सामाज्य जीवन की ओर आगे बढ़ने का भी प्रतीक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड और दूसरे नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकारें भी इस पहल से प्रेरित होंगी। लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक हैं। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

# कलेक्टर ने देवगांव के पीएम श्री पोर्ट केबिन स्कूल का किया निरीक्षण

# खनिज रेत के निगरानी हेतु ड्रोन तकनीक का उपयोग



ककड़ा जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए खनिज विभाग द्वारा अत्याधुनिक तकनीक ड्रोन कैमरा का उपयोग की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए खनिज अधिकारी सनत साहू ने बताया कि गत दिवस बुधवार रात्रि के दरमियान चारामा से लेकर ककड़ा क्षेत्र में प्रवाहित नदियों में ड्रोन कैमरे के माध्यम से औचक निगरानी रखते हुए कार्यवाही की गई। ड्रोन द्वारा मचांद्रा, माहुद, भिलाई, तेलगुडा, नगर पंचायत चारामा, जैसाकर, धिरोद, करिहा, सराधुनवागांव, हाराहुला, खरथा, बांडटोला, भुईगांव, किलेपार, टाहकापार, अरोद, तारसागांव, नाग, धिरावाही, माकडी, माटवाड, मुड़डोगरी, कोकपुर देवरी क्षेत्र का सर्वे किया गया। चारामा तहसील अंतर्गत ग्राम खस्था में 01 ट्रेक्टर न्यू

शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रावास की सुविधाओं और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निर्देश

नारायणपुर। कलेक्टर नम्रता जैन ने देवगांव स्थित पीएम श्री पोर्ट केबिन स्कूल का निरीक्षण कर विद्यालय एवं छात्रावास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने, परिसर में स्वच्छता बनाए रखने तथा आवश्यक मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यालय भवन, कक्षाओं, बालक एवं कन्या छात्रावास, शौचालय, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब सहित अन्य कक्षाओं का अवलोकन किया। छात्रावास परिसर में कुछ स्थानों पर गंदगी पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल साफ-सफाई कराने और नियमित स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने मरम्मत योग्य भवनों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने तथा आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र प्रारंभ



कारण के निर्देश दिए। साथ ही उपयोग में नहीं आ रहे भवनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं बेहतर भवनों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए, ताकि उनकी पढ़ाई निर्बाध रूप से संचालित हो सके। कलेक्टर ने बालक एवं कन्या छात्रावास का निरीक्षण कर विद्यार्थियों के रहने, भोजन, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध कराने तथा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों को नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ही नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण अध्यापन सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय परिसर में स्वच्छ एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखने पर भी जोर दिया।

# सफलता की कहानी: जिले के पिनगुंडा नाला पर पुलिया निर्माण से ओरछा क्षेत्र को मिली बड़ी राहत

# भाटापारा में यातायात व्यवस्था समस्यामय पायदान सरयू साहित्य ने सौंपा ज्ञापन मांगा गया समाधान

नारायणपुर। जिले के ओरछा क्षेत्र के लोगों के लिए हर वर्ष बारिश का मौसम कठिनाइयों और परेशानियों का फर्या बने जाता था। पल्ले-छोटेडोंगर-ओरछा मार्ग पर स्थित पिनगुंडा नाला बरसात के दिनों में उभान पर आ जाता था, जिससे नारायणपुर और ओरछा के बीच संपर्क पूरी तरह टूट जाता था। तहसील मुख्यालय ओरछा सहित आसपास के अनेक गांवों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, प्रशासनिक कार्यों और दैनिक जरूरतों के लिए जिला मुख्यालय तक पहुंचने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। कई बार मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे, विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती थी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी बाधित हो जाती थी। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा पिनगुंडा नाला पर 6 बॉक्स (7.00 म 6.00 मीटर) बॉक्स ब्रिज के निर्माण का निर्णय लिया गया। लगभग 258.25 लाख रुपये की लागत से निर्मित इस पुलिया का निर्माण कार्य अब पूर्ण हो चुका है और इस पर आवागमन भी शुरू हो गया



है। पुलिया के निर्माण से वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान मिल गया है। अब वर्षा ऋतु में भी नारायणपुर से ओरछा तक का मार्ग निर्बाध बना रहेगा। पहले जहां बारिश होते ही लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था या लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ता था, वहीं अब वे सुरक्षित और सुगमता से अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं। इससे ग्रामीणों का समय और धन दोनों की बचत हो रही है। इस पुलिया के शुरू होने से ओरछा तहसील मुख्यालय और आसपास के गांवों का जिला

मुख्यालय से संपर्क लगातार बना रहेगा। मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिलेगी, विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित नहीं होगी और शासकीय योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों तक आसानी से पहुंचेगा। साथ ही कृषि उपज और अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में भी सुविधा मिलने से स्थानीय व्यापार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण को क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उनका कहना है कि वर्षों से जिस समस्या का सामना पूरा क्षेत्र कर रहा था, उसका समाधान अब संभव हो पाया है। यह पुल केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का सेतु बन गया है। पिनगुंडा नाला पर निर्मित यह पुलिया शासन की जनहितैषी सोच और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। इस महत्वपूर्ण निर्माण से ओरछा क्षेत्र के हजारों लोगों का जीवन अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बना है तथा क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिली है।

भाटापारा। यातायात व्यवस्था एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रकल्प है जिससे शहर की समूची व्यवस्था प्रभावित होती है यदि यातायात व्यवस्था ठीक हो तो शहर व्यवस्थित एवं विकसित नगर आता है इसके अभाव में अन्य सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं एवं क्षेत्र के पिछड़ेपन को अभिव्यक्त करती हैं, भाटापारा में कुछ ऐसे ही माहौल के दर्शन होते हैं एवं क्षेत्र अव्यवस्था को बानगी प्रस्तुत करती नजर आती है। प्रमुख स्थलों में भीड़भाड़ एवं अव्यवस्था का नजारा: शहर के प्रमुख स्थल जहां अहम जन सरोकार के दृश्य नजर आते हैं उन स्थलों में अव्यवस्था का नजारा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, प्रमुख चौक चौहौ प्रमुख बाजार एवं क्षेत्र की अहम सड़कें भीड़ भाड़ एवं वाहनों के बेतरतीब जमावड़े का दृश्य प्रस्तुत करती हैं, खासकर हटरी बाजार एवं सदर बाजार के परिक्षेत्र घोर अव्यवस्था के शिकार



नजर आते हैं इसके अलावा रेट्ट हाउस से लेकर नाका नंबर एक का गौरवपथ मार्ग जहां विभिन्न विद्यालय अस्पताल एवं कार्यालय स्थापित हैं वहां भी स्थिति अव्यवस्थित ही नजर आती है, इन सन विद्युतनाओं के बीच हार्ड स्पॉट बाईक चालन एवं प्रेशर हार्न की समस्या भी दिखाई देती है जो अव्यवस्था के साथ ही दुर्घटनामय जोखिम का दृश्य प्रस्तुत करती हैं। परिषद के सदस्यों द्वारा भाटापारा के यातायात परिस्थिति को विस्तार से

अभिव्यक्त किया गया जिस पर पार्षद संवेदना का परिचय देते हुए यातायात थाना प्रभारी द्वारा इस दिशा में निरंतर कार्यवाही की जानकारी देते हुए शहर के प्रमुख बाजार में अव्यवस्था के संबंध में उन्होंने यही कहा कि जल्द ही व्यापारियों के बैठक आयोजित करने की रूपरेखा बनाई जाएगी एवं बाजार में व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशों का निर्धारण किया जाएगा। हार्डस्पॉट बाईक चालन एवं प्रेशर हार्न के संबंध में उन्होंने

यही कहा कि कार्यवाही निरंतर जारी है, साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस दिशा में त्रिनयन एप भी संचालित किया जा रहा है जिसमें जनमानस जागरूकता का परिचय देते हुए ऐसी विडियोनाओं की जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए सभी की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, उनके द्वारा परिषद की इस जागरूकतामय पहल को सराहना भी की गयी।

# उड़ीसा से उत्तरप्रदेश ले जाया जा रहा था 214.300 किलो गांजा, नगरनार पुलिस ने तस्क़र को दबोचा

# 'नवाजतन' नवाचार से मिली शिक्षा की नई दिशा, एफएलएन में शत-प्रतिशत दक्षता

जगदलपुर। बस्तर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना नगरनार क्षेत्र में 214.300 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। जब गांजे की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 7 लाख 15 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार, मुख्यालय से सूचना मिली थी कि उड़ीसा से एक सफेद महिन्द्रा बोल्लेरो पिकअप (क्र 52-ज़-2094) में गांजा लेकर दो व्यक्ति घनपुंजी के रास्ते जगदलपुर की ओर आ रहे हैं। सूचना के



आधार पर घनपुंजी फ़ैस्ट नाका के पास नाकाबंदी की गई। संदिग्ध वाहन को रोकेते ही उसमें सवार एक व्यक्ति जंगल की ओर भाग निकला,

जबकि चालक को पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विजय पाण्डेय (34 वर्ष), निवासी राजेन्द्र नगर पश्चिम, थाना गोरखनाथ, जिला गोरखपुर (उत्तरप्रदेश) के रूप में हुई है। पूछताछ में फार आरोपी का नाम सोनू यादव, निवासी गोरखपुर (उत्तरप्रदेश) बताया गया। वाहन की तलाशी में 9 प्लास्टिक बोरेटों में भरे 105 पैकेट गांजा, कुल वजन 214.300 किलोग्राम, बरामद किया गया। इसके अलावा गांजा परिवहन में प्रयुक्त महिन्द्रा बोल्लेरो पिकअप, एक सैमसन मोबाइल फोन और 700 रुपये नकद भी जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ

एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख)(द्व) (ग) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया, जबकि फार आरोपी की तलाश जारी है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग तथा नगर पुलिस अधीक्षक सुमीत कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने की। कार्रवाई में उपनिरीक्षक सतीश यदुराज, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक दीपक कुमार सिंह सहित थाना नगरनार एवं डीएसएफ के पुलिसकर्मीयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

चांपा। शासकीय प्राथमिक शाला सोटी में शिक्षिका ममता जायसवाल द्वारा शुरू किए गए नवाजतन नवाचार ने शाला की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी है। इस नवाचार के 6 सूत्रीय क्रियाव्ययन से शाला के कक्षा तीसरी के सभी छात्र फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरीसी एफएलएन में शत-प्रतिशत दक्ष हो गए हैं। एफएलएन सह नवाजतन कार्यक्रम के तहत शिक्षिका द्वारा अपनाए गए 6 बिंदु छात्रों के लिये कारगर साबित हुआ। बच्चों खुद से इस नवाचार पर काम करने लगे



जिसका सार्थक परिणाम मिला है। ममता जायसवाल ने बताया कि इसमें मुख्य रूप से बच्चों को स्वयं से सीखने के लिए प्रेरित किया गया वे इस पर काम भी किये। इसके बाद उन्हें और अधिक सीखने के लिए

# निर्माणधीन एनएच 343 का कलेक्टर ने लिया जायजा, लोगों में बेहतर कार्य की जगी उम्मीद

# चारामा पुलिस ने चोरी के तीन मामलों का किया सफल खुलासा



रामानुजगंज। जिले की कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने निर्माणधीन राष्ट्रीय राजमार्ग बलरामपुर से लेकर रामानुजगंज तक चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। निर्माणधीन सड़क पर उड़ने वाली धूल को रोकथाम के लिए नियमित रूप

से पानी का छिड़काव साथ ही सड़क का निर्माण स्वीकृत एलाइमेंट के अनुरूप और कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यकतानुसार मैनपावर बढ़ाने के निर्देश दिए गए। और कहा कि जिन स्थानों पर बीटी वर्क पूर्ण हो चुके हैं वहां डबलरीकरण का कार्य शुरू करें। इस दौरान एसडीएम अभिषेक गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी एनएच निरखिल लकड़ू सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

**अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट का किया निरीक्षण**  
उन्होंने अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए चेक पोस्ट पर संचालित जांच पंजी का अवलोकन किया तथा प्रतिदिन की जा रही जांच प्रक्रिया तथा तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति और उनके कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने खनिज एवं कृषि उपज मंडी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चेक पोस्ट से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की सघन एवं बारीकी से जांच सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी प्रकार के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

**चिकित्सकों की उपलब्धता करे सुनिश्चित**  
कलेक्टर ने 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए ओपीडी, ऑपरेशन थियेटर, प्रसव कक्ष एवं पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी देखी तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते कहा कि मरीजों के उपचार, ड्यूटी निर्वहन अथवा स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

**जिला जेल का भी किया निरीक्षण**  
इस दौरान कलेक्टर संजय चंदन त्रिपाठी ने जिला जेल का औचक निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बैरकों, रसेईंगर और अस्पताल का जायजा लिया। कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं और समस्याओं को जानने के लिए बंदि्यों से सीधी बातचीत की और जेल प्रशासन को सुरक्षा व स्वच्छता सुधारने के निर्देश दिए।



संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की बात स्वीकार की। आरोपियों ने बताया कि चोरी किए गए सामान का आपस में बांटवारा कर लिया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में से मुख्य आरोपी सूरज देवान, जो निगरानी बंदशर है, के खिलाफ कई पुराने अपराध दर्ज हैं, जिनमें से कुछ जिला बंदर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी चोरी और संबंधित अपराधों के मामले दर्ज हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। इस सफलता में थाना चारामा और जिला

सायबर सेल ककड़ा के संयुक्त टीम का विशेष योगदान रहा है। टीम के सदस्यों में निरीक्षक सुरेश कुमार राठौर, साइबर प्रभारी यशवंत श्याम, उप निरीक्षक रूपेन्द्र पटेल, हेमंत कुमार, दुष्यंत दीवान, आरक्षक तरुण सिन्हा, फानू, भकेश पटेल, सचिन सोरी, रामरतन निषाद और जितेंद्र नाग शामिल हैं। ककड़ा पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि घर और दुकानों की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि अपराधों को रोक जा सके। पुलिस की ओर से बताया गया है कि सूचनाकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा।



## कनेर के पौधे को घर में लगाने के कई फायदे

**ज्यो** तिथि और वास्तु शास्त्र में कई पेड़-पौधों का उल्लेख है। जिन्हें घर में लगाना अनुकूल माना जाता है। कुछ पौधों को घर पर नहीं लगाना चाहिए। क्या कनेर का पौधा घर के लिए शुभ है। क्या कनेर के पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स से जानते हैं।

कनेर के पौधे का संबंध देवी लक्ष्मी से माना जाता है। कनेर के पौधे को घर में लगाने से धन की देवी का वास स्थापित होता है। घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति और बाधा दूर हो जाती है। कनेर के पौधे को घर में लगाने से शुभता बढ़ती है। धन लाभ के योग बनते हैं। अटका हुआ काम जल्दी पूरा हो जाता है। घर में सकारात्मकता बढ़ती है। वास्तु दोष भी दूर होने लगता है।

कनेर के पौधे को घर में लगाने से सुख, समृद्धि और संपन्नता का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, सफेद और पीले रंग के कनेर का फूल घर में लगाना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर में लाल रंग के कनेर फूल वाले पौधा नहीं लगाना चाहिए। लाल रंग का कनेर अशुभ होता है। कनेर और पीले रंग के पौधे को घर में पश्चिम या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए।

**बा** रिश के मौसम में फंगल और बैक्टीरिया पनपने के चांस बढ़ जाते हैं। गीले कपड़े और चारों तरफ फैली चिपचिप रिस्किन पर भी असर दिखाती है। नमी की वजह से रिस्किन पर भी पसीना और ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जिसकी वजह से गंदगी और प्रदूषण ज्यादा अटैक होते हैं और कई बार लोगों को फोड़े, फुन्सी निकलना शुरू हो जाती है। इन फोड़े और फुन्सी में हल्के पीले रंग का लिक्विड या पस भरा होता है। जो बेहद दर्दनाक होता है और कई बार ये ज्यादा दिनों तक ठीक नहीं होता। अगर रिस्किन पर फोड़े और फुन्सी बारिश में हो जाते हैं तो इस घरेलू नुस्खों से ठीक किया जा सकता है। फोड़े-फुन्सी ठीक करने का सरल घरेलू तरीका...

## बारिश के मौसम में फंगल और बैक्टीरिया से निपटने के उपाय

बारिश में हाथ, पैर, बगल, जांच या शरीर के बाहरी हिस्से पर फोड़े या फुन्सी हो गईं हैं तो इसे ठीक करने के लिए बहुत आसान सा घरेलू उपाय अपनाएं। ये फोड़े तो पस को बाहर निकालकर सुखाने में मदद करता है।

गाय के शुद्ध देसी घी और हल्दी को मिलाकर लेप तैयार कर लें। इस लेप को फोड़े या फुन्सी के ऊपर लगाएं। एक ही रात में हल्का सा गर्म कर फोड़े के ऊपर लगा दें। कम से कम दो बार दिन में लगाएं और एक से दो दिन में ही फोड़े खत्म हो जाएंगे और दर्द से भी आराम मिलेगा।

सर्जरी के बाद अगर किसी तरह की सर्जरी हुई है, तो उसके तुरंत बाद या बॉडी में स्टिचिंग लगे होने पर स्वीमिंग नहीं करनी चाहिए, वरना समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर शरीर में कहीं घाव है, तो भी पूल में जाने से बचना चाहिए। वरना पानी में भीगने से घाव गंभीर बन सकता है।

**ख** जूर में हाई फाइबर और एंटी ऑक्सीडेंट्स जैसे गुण होते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) भी काफी कम होता है, जिससे यह सेहत के लिए जबरदस्त फायदेमंद माना जाता है। खजूर में हाई फाइबर और एंटी ऑक्सीडेंट्स जैसे गुण होते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) भी काफी कम होता है, जिससे यह सेहत के लिए जबरदस्त फायदेमंद माना जाता है।

1. सेहतमंद रहने के लिए खानपान का खास ख्याल रखना चाहिए। अच्छी डाइट से कई तरह की परेशानियां दूर की जा सकती हैं। कई झाड़ फूटस सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। उनमें से एक खजूर भी है, जिसके अनभिन्न फायदे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर रोजाना सुबह खाली पेट सिर्फ 3 खजूर खाए जाएं तो कमाल के फायदे मिलते हैं।
2. डाइजैस्टिव हेल्थ के लिए खजूर बेहद फायदेमंद है। खाली पेट भीगे खजूर खाने से कब्ज, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याएं घूमंतर हो सकती हैं। डाइटरी फाइबर से भरपूर होने के चलते खजूर बेहद फायदेमंद होता है। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर पावन को बेहतर बनाता है। इससे पेट भी साफ रहता है।
3. सुबह-सुबह खाली पेट सिर्फ 3 भीगे खजूर खाने से दिनभर पनजैटिक रहने में मदद मिलती है। खजूर में हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेन्ट, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज जैसे नेचुरल शुगर पाए जाते हैं, जो तुरंत पनजी देते हैं। एक रिसर्च के अनुसार, खाली पेट 3 खजूर खाने से सहनशक्ति बढ़ती जाती है।
4. हर दिन सुबह तीन खजूर खाने से हार्ट की सेहत दुरुस्त होती है। रिसर्च में भी पाया गया है कि खजूर बेड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर दिल के खतरे को कम कर सकता है। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, खजूर में एंटीऑक्सीडेंट एलडीएल है, दिनभर की सुस्ती दूर होती है।
5. खजूर पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है, जो तंत्रिका को काम करने में मदद करता है। रोजाना खजूर खाने से दिमाग दुरुस्त रहता है। याददाश्त बढ़ती है। इससे ओवरऑल ब्रेन हेल्थ को फायदा होता है।
6. उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ऐसे में खजूर फायदेमंद हो सकता है। खजूर में कैल्शियम,

## तनाव होने पर वॉक करना फायदेमंद

**का** म का प्रेस, बिगडी लाइफस्टाइल की वजह से तनाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई तरह की फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यू होते हैं। ऐसे में वॉक करना फायदेमंद हो सकता है।

एक्सपर्ट्स वॉकिंग को ब्रेन बूस्टर मानते हैं। इससे दिमाग बढ़ा होता है और याददाश्त बेहतर होती है। एक रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि टहलने से बुजुर्गों में डिमेंशिया और अल्जाइमर के रिस्क भी कम होता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि कटीब 10 मिनट तक तेज चलना भी नकारात्मक विचारों को भगाने का काम करता है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि रोजाना 10 हजार कदम चलने से दिल, दिमाग और शरीर दुरुस्त रहते हैं।



**टहलने से दिमाग को जबरदस्त फायदा** डिजीज के अनुसार बताया गया है कि रोजाना कुछ कदम चलकर या थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से दिमाग की साइज बढ़ सकती है। इसका मतलब दिमाग हेल्दी रहता है। उसके सभी न्यूरोट्रांसमिटर सही तरह काम करते हैं। ऐसे लोगों को मतलब डिमेंशिया या अल्जाइमर का खतरा नहीं रहता है।

**टहलने से एंजाइटी कम** होता है एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर दिन मॉडरेट एक्सरसाइज करने से ब्रेन पर सकारात्मक असर होता है। रोजाना 20 से 30 मिनट टहलने से तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी का लेवल कम होता है। इस दौरान

शरीर में एंडोर्फिन हॉर्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे तनाव घूमंतर होता है और आप अच्छे महसूस करते हैं।

**मूड अच्छा** होता है एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिन में कुछ मिनट चलने से ही मूड अच्छा बन सकता है। इससे एंजाइटी कम हो सकती है। वॉकिंग का

असर तब काफी ज्यादा हो जाता है, जब आप प्रकृति में टहलें। चलने से मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं और इनका स्ट्रेस कम होता है। टहलने से नींद बेहतर होती है और शरीर सेहतमंद रहता है।

**क्या टहलना कसरत का विकल्प है?**  
टहलना एक तरह की कसरत है और यह बहुत प्रभावी भी है। इसे अक्सर ज्यादा तीव्र व्यायाम के पक्ष में अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन टहलने से कई हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तु अगर आप किसी तरीके की एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो आप टहलने को फिटनेस का एक विकल्प बना सकते हैं।

## सिल्क की साड़ी के साथ बनवाएं इस डिजाइन के ब्लाउज

**सि** ल्क की साड़ी पहनना चाहती हैं, लेकिन सोच रही हैं कि वही बोरिंग लुक मिलेगा। तो जरा इन झूटीफुल एक्ट्रेसज के लुक पर नजर डाल लें, जिसमें वो अट्रैक्टिव ब्लाउज डिजाइन को पहने दिख रही हैं। सिल्क की साड़ी के साथ सिंपल डिजाइन के ही नहीं बल्कि इन तरीकों के ब्लाउज को बनवा सकती हैं। जो काफी खूबसूरत दिखते हैं और आपके सिल्क की साड़ी के साथ भीड़ में हटके बनाने में मदद करेंगे।

**पस बाहर निकलने में मदद मिलेगी, लेकिन इस लेप को कम से कम दो से तीन दिन लगाएं।** जिससे कि पस और फोड़े को सूखने में मदद मिले। साथ ही रिस्किन पर धब्बे भी ना रह जाएं।

दूसरा उपाय भी काफी सरल है और छोटें फोड़े और फुन्सी पर असर करता है। जैसे ही फोड़े की शुरुआत हो वैसे ही गाय के शुद्ध देसी घी को

**एंग्रायडरी वाले ब्लाउज** अगर आप मैचिंग के सिल्क पेट्टन के ब्लाउज को नहीं पहनना चाहती हैं, तो एंग्रायडरी वाले कपड़े पर साड़ी के मैचिंग का बॉर्डर लगा सकते हैं। ये हटके ब्लाउज खूबसूरत दिखता है।

**हाफ स्लीव और बैकलेस डिजाइन** मैचिंग के ब्लाउज के कपड़े को बगवाते समग्र ब्लाउज की डिजाइन पर फोकस करें। बैकलेस, यू शोप, राउंड शोप या डोरी वाले ब्लाउज बनवाएं। अगर

आप किसी नई तरह की डिजाइन को ट्राई करना चाहती हैं तो जरूर करें। ये आपकी साड़ी को भीड़ में हटके लुक देगी।

**फफ स्लीव** साउथ इंडियन वाला लुक चाहिए तो फफ स्लीव ब्लाउज बना सकते हैं। वैसे तो सिल्क फैब्रिक के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट ब्यूटीफुल नहीं लगेंगे, लेकिन प्लैट्स डले फफ स्लीव डिजाइन को ट्राई कर सकती हैं।

## हिंदू धर्म में रसोई घर का बहुत महत्व

**स्वा** ने से लेकर सोने तक वास्तु शास्त्र में कई तरह के नियम बताए हैं। इन नियमों का पालन करके व्यक्ति एक खुशहाल जीवन जीता है। इसी तरह हिंदू धर्म में रसोई घर को बहुत महत्ता दी गई है। इसे एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहां बना हुआ खाना व्यक्ति को जीवन व्यतीत करने की शक्ति देता है। हर दिन रोटी बनाई जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार रसोई में बनाई जाने वाली रोटी से जुड़े नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। वरना घर में बरकत नहीं रहती है। साथ ही कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं।



**इस दिन नहीं बनानी चाहिए रोटी** एकादशी के व्रत के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। वही, दिवाली, शरद पूर्णिमा, शीतलाष्टमी, नागपंचमी और किसी की मृत्यु पर घर में रोटी नहीं बनाई जाती है। इस नियम को न मानने पर मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। ऐसे लोगों को अन्न और धन की कमी होने लगती है।

**गिनकर न बनाएं रोटी** रोटी बनाने से पहले अपने परिवार के सदस्यों से पूछना कि वे कितना खाएंगे या रोटी खिलाते या खाते समय रोटी गिना, यह बहुत ही गलत आदत है। हिंदू मान्यता में इसे शुभ नहीं माना जाता है। रोटी का संबंध सूर्य से होता है और जब आप इसे गिनकर बनाते हैं, तो आप सूर्य देव का अपमान करते हैं। ऐसे

में तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

**रोटी बनाते समय दिशा का ध्यान रखें** रोटी बनाते समय कुछ वास्तु नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस वृत्त पर आप खाना बनाते हैं, वह आपकी रसोई के दक्षिण-पूर्व कोने यानी आग्नेय कोण में होना चाहिए। रोटी बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए।

**पहली रोटी गाय को दें** रसोई में बनी पहली रोटी हमेशा गाय को देनी चाहिए। अगर गाय को नहीं खिला पाएं, तो पहली रोटी किसी कुत्ते को भी खिला सकते हैं। गाय या कुत्ते द्वारा रोटी खाने से उस घर में रहने वाले लोगों की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं।

## किसे नहीं करना चाहिए स्विमिंग

**स्वि** मिंग कई तरह की बीमारियों का इलाज है। यह सबसे अच्छी एक्सरसाइज में से एक है। यह कार्डियो एक्टिविटीज में आता है और बेहद असरदार है। स्वीमिंग करने से घुटने के दर्द, मोटापे जैसी समस्याएं दूर हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रोजाना केवल 30 से 40 मिनट स्वीमिंग करने से ही शरीर को सेहतमंद रख सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जब स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, वरना फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। स्वीमिंग कब नहीं करनी चाहिए..

**हाइपोग्लाइसीमिया** अगर किसी का शुगर लेवल लो रहता है तो उन्हें स्वीमिंग से बचना चाहिए। शुगर लेवल के हिसाब से डॉक्टर की सलाह पर ही ऐसी एक्सरसाइज का प्लान करना चाहिए। वरना स्वीमिंग के दौरान बेहोशी आ सकती है, जो खतरनाक हो सकता है।

**कंटेजियस बीमारियां** जुकाम, खांसी, रिस्किन और एलर्जी जैसी कंटेजियस डिजीज में स्वीमिंग से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में स्वीमिंग पूल में जाना अवॉयड करना चाहिए, वरना कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं।

**स्वीमिंग करने से पहले वर्कआउट करें** स्वीमिंग ही नहीं किसी भी वर्कआउट करने से पहले सबसे पहले उसकी बारीकियों को समझना और सीखना चाहिए। पहले कभी भी स्वीमिंग नहीं किया है, तो सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग लें और फिर इसे रोजाना की लाइफ में लाएं। इसके लिए बॉडी की जरूरत को भी समझना चाहिए। वृद्धि स्वीमिंग बकाने वाली एक्टिविटी है, ऐसे में अगर शरीर मजबूत नहीं है, तो फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है।

**पूल से होने वाले खतरे** डायरिया के अलावा, स्विमिंग से रिस्किन इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन और आंखों में संक्रमण भी हो सकता है। ये शरीर के वे अंग हैं जो सीधे वातावरण के संपर्क में आते हैं और ये ज्यादातर उन जीवों के कारण होते हैं जो स्वाभाविक रूप से पानी में रहते हैं। स्विमिंग पूल संक्रमण पैदा करने वाले आम जीव क्रिप्टोस्पोरिडियम, लैजिओनेला, स्क्रूडोमोनास, नोरोविरस, शिगेल्ला, ई. कोली और गिनाइडिया हैं।

## खाली पेट खाएं खजूर

कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोकने के गुण पाए जाते हैं, जिससे घमनियां में प्लाक बनना कम होता है और दिल की सेहत दुरुस्त रहती है।

**5.** खजूर पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है, जो तंत्रिका को काम करने में मदद करता है। रोजाना खजूर खाने से दिमाग दुरुस्त रहता है। याददाश्त बढ़ती है। इससे ओवरऑल ब्रेन हेल्थ को फायदा होता है।

**6.** उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ऐसे में खजूर फायदेमंद हो सकता है। खजूर में कैल्शियम,

फॉस्फोरस और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार फाइबर से भरपूर होने के चलते खजूर बेहद फायदेमंद है। नियमित तौर से खजूर खाने से हड्डियों को जबरदस्त फायदा होता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है।

# गाजीपुर में सक्षम का स्थापना दिवस संपन्न

पंकज बने नए प्रांतीय मुख्य वक्ता और नई कार्यकारिणी घोषित

गाजीपुर। सम दृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल (सक्षम) काशी प्रांत का स्थापना दिवस रविवार शाम चितनाथ घाट स्थित आर्य समाज मंदिर के सभागार में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला संघचालक जयप्रकाश, जिला प्रचारक प्रभात और शंकर पाण्डेय ने भारत माता, अष्टवक्र और सूरदास के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया।

18 वर्षों से दिव्यांगों की सेवा में समर्पित- जिला प्रचारक प्रभात ने बताया कि द्वितीय सर संघचालक सदाशिव राव गोलवलकर 'गुरुजी' की परिक्ल्पना पर भैयाजी जोशी ने 20 जून 2008 को नागपुर में सक्षम की स्थापना की थी। अपने 18 वर्षों के सफर में यह संगठन देश भर में दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। प्रयागराज कुंभ मेले में आयोजित 'नेत्र कुंभ' के माध्यम से लाखों दृष्टि दिव्यांगों का उपचार कर संगठन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था।

विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग सेवा संगठन- प्रांतीय मुख्य वक्ता पंकज ने कहा कि सक्षम अपने 7 प्रकोष्ठों के माध्यम से दिव्यांगों के कल्याण के लिए काम करने वाला विश्व का सबसे बड़ा सेवा संगठन बन चुका है। प्रांत महिला प्रमुख राधा सिंह ने भी कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला संघचालक जयप्रकाश ने की।



मुख्य वक्ता पंकज ने संगठन की नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की, जिन्हें मौके पर दायित्व ग्रहण कराया गया। जिलाध्यक्ष: धर्मेन्द्र दूबे, जिला उपाध्यक्ष: कन्देष्टा उपाध्याय, जिला सचिव: जयशंकर राय, जिला सह

सचिव रूपेश सिंह। इस अवसर पर कृपाशंकर राय, वित्तिन अग्रहरी, स्वप्निल राय, नीरज कुमार उर्फमानू, संकटमोचन पुजारी अंजनी और विजय नारायण राय सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

# बारिश के मौसम में सर्पदंश के मामले बढ़े, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

संभागीय संयुक्त संचालक डॉ. अनिल शुक्ला ने अस्पतालों में एंटी-स्नेक वेनम रखने के लिए सख्त निर्देश

अंबिकापुर (लोकतंत्र प्रहरी)। बारिश के मौसम के शुरू होते ही सर्पुजा संभंग में मौसमी बीमारियों और सर्पदंश (सांप काटने) के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के संभागीय संयुक्त संचालक डॉ. अनिल शुक्ला ने संभंग के अंतर्गत आने वाले सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) को इसकी रोकथाम और त्वरित इलाज के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।



वर्षा ऋतु में संक्रमण का खतरा अधिक - डॉ. शुक्ला ने बताया कि वर्षा ऋतु के दौरान संक्रमण और मौसमी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। ऐसे में सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों के लिए बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करना बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपातकालीन दवाओं का होगा पर्याप्त भंडारण- संभागीय संयुक्त संचालक ने संभंग के अपने-अपने जिलों के सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में एंटी-स्नेक वेनम (सांप के जहर की काट) के साथ-साथ अन्य जरूरी जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक (भंडारण) सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके और किसी भी जान न जाए।

# अमलेश्वर में अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का अभियान, दुकानदारों को मिला अंतिम समय, फिर चलेगी बुलडोजर

अमलेश्वर। अमलेश्वर नगर पालिका क्षेत्र में लंबे समय से चर्चा का विषय बने अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। अमलेश्वर नगर पालिका और पाटन प्रशासन की संयुक्त टीम संबंधित स्थानों पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। जानकारी के अनुसार, नगर में कई स्थानों पर लंबे समय से अवैध कब्जे किए गए हैं। कुछ लोगों द्वारा मैदानों में नेकर टाइल्स लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। प्रशासन की ओर से पहले भी नोटिस जारी कर कब्जाधारियों को समय दिया गया था, लेकिन कई लोग अब भी कब्जा हटाने की तैयारी नहीं हुए हैं। नगरवासियों का कहना है कि संबंधित स्थल से लेकर अटल चौक तक बड़े-भू-भाग पर अतिक्रमण किया गया है, लेकिन राजस्व विभाग अब तक



सख्त कार्रवाई करने से हिचकता नजर आ रहा है। वहीं, नगर के रोज हिस्सों जैसे पाहंद रोड, खुदमुडू रोड और शीतला विहार रोड में भी अवैध कब्जों की शिकायतें सामने आ रही हैं। कार्रवाई के दौरान जब अतिक्रमण हटाने की बारी आई तो दुकानदारों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि उनकी दुकानों में रखा कीमती सामान सुरक्षित निकालने के लिए कुछ समय दिया जाए। इस पर तहसीलदार पवन

ठकुर, नगर पालिका अध्यक्ष दयानंद सोनकर और अमलेश्वर नगर पालिका के इंजीनियर डालेंद्र सिंह ठकुर ने दुकानदारों को अंतिम समय प्रदान किया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में खारुन नदी महादेव घाट से थाना चौक तक सड़क किनारे गुमटी लगाकर दुकानदारी किए जाने के

# अमलेश्वर के राजनीति में उबाल, शिवसेना के प्रदेश सचिव, छाया पालिका अध्यक्ष, हिमांशु शर्मा ने थामा कांग्रेस का दामन, 65 युवा साथियों के साथ ली सदस्यता

अमलेश्वर। शिवसेना के प्रदेश सचिव एवं नगर पालिका परिषद अमलेश्वर के छाया नगर पालिका अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं दुर्ग जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने अमलेश्वर नगर पालिका क्षेत्र से हिमांशु शर्मा सहित उनके साथ आए 65 युवा साथियों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई।



हिमांशु शर्मा ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी की नीतियों और जनहित के मुद्दों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके कांग्रेस में शामिल होने से अमलेश्वर नगर पालिका की राजनीति में नया समीकरण बनता नजर आ रहा है और नगर में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। नगर के लोगों के बीच

नजर आ रहा है। वहीं, अमलेश्वर नगर पालिका में तयकथित ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद विकास कार्यों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के पार्षदों ने पूर्व में अवैध कब्जों सहित विभिन्न मांगों को लेकर पालिका की बैठक का बहिष्कार भी किया था। बावजूद इसके, अवैध कब्जों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बनी हुई है। ऐसे में हिमांशु शर्मा के कांग्रेस में प्रवेश के बाद नगर की राजनीति में नई सफाई आने की संभावना जताई जा रही है।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किस प्रकार एकजुट होकर जनहित के मुद्दों को उठाती है और भाजपा सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को और मुखर करती है।

# नवनि्युक्त एलडरमेनो ने सांसद विजय बघेल से की मुलाकात, जताया आभार

कुम्हारी। नगर पालिका परिषद कुम्हारी में एलडरमेन पार्षद की नियुक्ति हुई है। जिसमें प्रणव श्रीवास्तव (बंकी), अक्षयेश शुक्ला, गोल्डी गोस्वामी, सुनीता कुंरें एवं मनहरण साहू शामिल हैं। मनोनीत समस्त एलडरमेन ने लगातार भाजपा में अपनी सेवाएं दी हैं इनमें प्रणव श्रीवास्तव सबसे कम उम्र के युवा हैं। नवनि्युक्त सभी एलडरमेन ने सांसद विजय बघेल से औपचारिक मुलाकात की। इसकी नियुक्ति पर नगर के समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। नवनि्युक्त एलडरमेनो को बधाई देने वालों में मीना वर्मा पालिका अध्यक्ष, राजू निषाद सांसद



प्रतिनिधि, धर्मेन्द्र सिन्हा मंडल अध्यक्ष, छिकेश पटेल पार्षद, अमाकत साहू पार्षद, अश्वनी देशलहरे पार्षद, लोकेश साहू पार्षद, ओंकार मार्कण्डेय पार्षद, प्रवीण राव पार्षद, मिथिलेश यादव सांसद प्रतिनिधि, सुजीतो यादव सांसद प्रतिनिधि, गिरीश सोनी, सूरज यादव, पंकज वर्मा, दीपक बैस, गोविंद बघेल, अन्य साथी कार्यकर्ता मित्रगण शामिल हैं। सभी ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया एवं दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल, एवं दुर्ग जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, वरिष्ठ भाजपा नेता शशिकांत बघेल एवं संजय बघेल से मुलाकात कर आभार जताया।

# ग्राम कुथरेल में सामुदायिक मध्यस्थता अभियान की शुरुआत ग्रामीणों को दिया गया विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान का संदेश

दुर्ग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरिंग प्रोसीजर्स, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा ग्राम कुथरेल में सामुदायिक मध्यस्थता विषयक कार्यकलाप एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायालयीन वादों की संख्या में कमी लाने हेतु स्थानीय स्तर पर आपसी संवाद एवं सहमति के माध्यम से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत (जनेपयोगी सेवाएं), दुर्ग की अध्यक्ष सुष्मा लकड़, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर तथा वरिष्ठ न्यायालय प्रबंधक ने ग्राम पंचायत भवन में आयोजित बैठक में ग्रामीणों, जनेपयोगी, महिला समूहों, पैरालील वालांटियर्स, युवा एवं गणमान्य नागरिकों से संवाद किया। अपने संबोधन में स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत (जनेपयोगी सेवाएं), दुर्ग



की अध्यक्ष सुष्मा लकड़ ने कहा कि सामुदायिक मध्यस्थता न्यायालयीन प्रक्रिया का विकल्प नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने वाला एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि अधिकार स्थानीय विवाद संवाद, समझदारी एवं निष्पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त किए जा सकते हैं, जिससे समय, धन एवं श्रम की बचत होने के साथ-साथ प्रारंभिक एवं सामाजिक संघर्ष की सुरक्षित रहते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत,

# मासिक व तिमाही परीक्षा में संतोषप्रद परिणाम आने पर प्राचार्यों व व्याख्याताओं पर गिरेगी गाज

बेमेतरा। जिला पंचायत बेमेतरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेमलता पद्माकर की अध्यक्षता में शिक्षा जिला बेमेतरा के हाईस्कूल सत्र 2025-26 परीक्षा परिणाम 50% से कम आने वाले विद्यालय के प्राचार्य एवं संस्था के समस्त व्याख्याताओं तथा कक्षा 12वीं में 75% से कम आने वाले प्राचार्यों एवं समस्त व्याख्याताओं का जिला पंचायत बेमेतरा के सभागार में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेमलता पद्माकर द्वारा सभी प्राचार्यों एवं समस्त व्याख्याताओं से परीक्षा परिणाम कम आने तथा परिणाम के कारण सहित समीक्षा की गई। सभी प्राचार्यों को टीचिंग से बचने समझ पा रहे हैं उनका आकलन करने, मासिक टेस्ट करने, क्लासरूम में आने से पहले विषय की तैयारी करके आने, कमजोर बच्चों की तैयारी, बच्चों की नियमित उपस्थिति, कमजोर बच्चों



के लिए प्रतिदिन होमवर्क, एवं उनकी सतत निगरानी करने हेतु निर्देश दिया गया। सत्र 2026-27 में हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम 80% तथा कक्षा 12वीं का 90% लाने का लक्ष्य निर्धारित करने हेतु निर्देश दिया गया। द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा 2026 में बच्चों का परीक्षा 100% परिणाम लाने का निर्देश दिया गया। इस हेतु विषय की अवधारणा की समझ विकसित करना उन्होंने जरूरी बताया। ताकि बच्चे परीक्षा में दिए गए प्रश्नों का उत्तर सचरूप से सुनिश्चित करने हेतु विशेष शिक्षकों को निर्देश दिया गया। मासिक परीक्षा एवं तिमाही परीक्षा में विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम संतोषप्रद ना आने पर प्राचार्य एवं विषय शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया। साथ ही पाठ्यक्रम पूर्ण करने की एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर गठित कोर ग्रुप समिति तथा विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रश्न पत्र का निर्धारण करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल, जिला मिशन समन्वयक (डीएमसी) नकुल प्रसाद पनागर उपस्थित रहे।

# टिकेश्वर साहू बने छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनिन के कबीरधाम जिला सह सचिव

कवर्धा। पत्रकार टिकेश्वर साहू को पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी सक्रिय भूमिका, संगठन के प्रति समर्पण एवं निरंतर उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनिन का कबीरधाम जिला सह सचिव मनोनीत किया गया है। जिला अध्यक्ष श्याम टंडन ने उनके मनोवचन की घोषणा करते हुए कहा कि टिकेश्वर साहू लंबे समय से निष्पक्ष, निर्भीक और जनसरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता कर रहे हैं। संगठन को ऐसे कर्मठ और सक्रिय पत्रकारों की आवश्यकता है, जो पत्रकार हितों के साथ-साथ समाज के मुद्दों को भी मजबूती से उठाने का कार्य करें। उन्होंने विश्वास जताया कि टिकेश्वर साहू के अनुभव और कार्यशैली से संगठन को नई ऊर्जा एवं मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनिन के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर दुबे एवं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन पटेल के



निर्देशन एवं मार्गदर्शन में संगठन प्रदेशभर में लगातार विस्तार कर रहा है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन पटेल ने कहा कि संगठन पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद टिकेश्वर साहू जिले के पत्रकारों को संगठित करने, उनकी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने तथा संगठन की गतिविधियों को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का सशक्त स्तंभ है और पत्रकारों की

# गांडा समाज अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के शपथ ग्रहण की गवाह बने पूर्व कलेक्टर प्रदेश अध्यक्ष संरक्षक डीएफओ

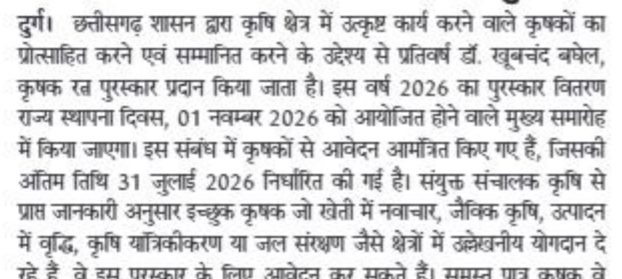
गरियाबाद। देवभोग ब्लॉक में निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए गांडा समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शेषनारायण सोनवानी सचिव यशवंत बघेल कोषाध्यक्ष दिगम्बर सर्वण एवं अन्य मनोनीत पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह मुख्यालय में हर्षोद्भव और गरिमाभय माहौल के बीच संपन्न हुआ समारोह में पुरुष एवं महिला वर्ग के साथ साथ युवा वर्ग के लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सर्व गांडा समाज के प्रदेश अध्यक्ष तेजराज जागदले, विशिष्ट अतिथि एवं कलेक्टर एवं प्रदेश संयोजक कुमार लाल चौहान प्रदेश संरक्षक एवं डीएफओ अशोक सोनवानी सविता नाग तथा क्षेत्रीय



विधायक जनक ध्रुव मौजूद रहे शपथ ग्रहण समारोह से पहले भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर एवं छत्तीसगढ़ महतारी के छायांचर पर पृष्ण अर्पित कर की गई इसके बाद अतिथियों का पारंपरिक स्वागत किया गया इसके बाद समाजिक लोगों को अतिथियों द्वारा बारी बारी से संबोधन कुमार लाल चौहान ने कहा कि देवभोग ब्लॉक के लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करार समाज ने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने कहा कि इस तरह की पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया

# डॉ. खूबचंद बघेल, कृषक रत्न पुरस्कार हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों का प्रोत्साहित करने एवं सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष डॉ. खूबचंद बघेल, कृषक रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस वर्ष 2026 का पुरस्कार वितरण राज्य स्थापना दिवस, 01 नवम्बर 2026 को आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में किया जाएगा। इस संबंध में कृषकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। संयुक्त संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी अनुसार इच्छुक कृषक जो खेती में नवाचार, जैविक कृषि, उत्पादन में वृद्धि, कृषि यांत्रिकीकरण या जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं, वे इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। समस्त पात्र कृषक वे निर्धारित तिथि तक आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक अर्हताएं एवं अन्य जानकारी संबंधित विकासखंड / जिला कृषि कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। कृषकों से प्रायः आवेदनों का सत्यापन संयुक्त संचालक कृषि द्वारा गठित विकासखंड स्तरीय छनबीन समिति द्वारा किया जाएगा। विकासखंड स्तरीय समिति कृषकों के प्रश्नों में जाकर आवेदन में उल्लेखित अधोसंरचना, कृषि आदान, सिंचाई संसाधन व अन्य जानकारी का प्रत्यक्ष निरीक्षण व अवलोकन सत्यापन उपरांत प्रतिवेदन जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा सूक्ष्म जांच उपरांत जिला से अधिकतम 03 उत्कृष्ट कृषकों का चयन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से नामांकन संचालनालय कृषि को उपलब्ध कराया जाएगा। कृषक रत्न पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रखर कृषक नेता डॉ. खूबचंद बघेल के नाम पर दिया जाता है।



युवाओं को लोकतंत्र की सही सीख देती है उन्होंने समाज से बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, हर वर्ष करियर गाइडेंस कार्यक्रम आयोजित करने तथा नई पीढ़ी को प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया साथ ही पूरे प्रदेश में गांडा समाज को संगठित करने के प्रयास को भी बताया चौहान ने कहा कि बहुसंख्यक होने के बाद भी गांडा समाज राजनीतिक सहित तमाम हक अधिकार से वंचित है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ गांडा समाज का विखराव है इसलिए छत्तीसगढ़ फेडरेशन के तले पूरे गांडा समाज को एक करने का काम किया जा रहा है जिसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है।